हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

20 फरवरी, 1986

खण्ड 1, अंक 4

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 20 फरवरी, 1986

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(4)1
प्र न देने वाले सदस्यों की बजाये अन्य सदस्यों द्वारा प्र न पूछने की अनुमति देना	(4)10
तारांकित प्र न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(4)10
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र न का लिखित उत्तर	(4)20
गैर सरकारी प्रस्ताव– (i) भााह आयोग द्वारा हरियाणा के पक्ष में अवार्ड किये गये सभी क्षेत्रों को हरियाणा राज्य में ट्रांसफर करने संबंधी (पुनरारम्भ)	(4)21
(ii) पंजाब क्षेत्र में एस.वाई.एल. नहर के निर्माण में देरी संबंधी	(4)22
वक्तव्य– मुख्य मंत्री द्वारा सहायता प्राप्त गैर सरकारी महाविद्यालयों के अमले के वेतन की बैंकों द्वारा अदायगी संबंधी।	(4)38
गैर सरकारी प्रस्ताव (पुनरारम्भ)	(4)40

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 20 फरवरी, 1986

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की।

श्री अध्यक्ष: साहेबान, अब क्वै चन होंगे।

तारांकित प्र न सं0 1056

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री राम बिलास भार्मा, सदन में उपस्थित नहीं थे।

Development of Faridabad Complex

***1073. Shrimati Sharda Rani:** Will the Minster of State for Local Government be pleased to state:-

(a) whether the Government is aware of the fact that the development of the Faridabad Complex and its adjoining area is not being made under any proper planning;

(b) whether it is also a fact that the haphazard and unauthorized growth is going on in and around the Complex and the residents thereof are not getting the desired facilities; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Faridabad

Development Authority for the development of the aforesaid Complex ?

स्थानीय भाासन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रका ा महाजन):

(क) नहीं। फरीदाबाद कम्पलैक्स एडमिनिस्ट्रे ान वर्श 1972 में Faridabad Complex (Regulation and Development) Act, के अधीन इसलिए बनाया गया था कि फरीदाबाद में उचित, नियमित योजित प्रकार का विकास हो सके। फरीदाबाद कम्पलैक्स का उसकी निर्धारित सीमा के बाहर के क्षेत्र में कोई नियन्त्रण नहीं है।

(श्री ओम प्रका ा महाजन)

(ख) नहीं। फिर भी कहा जाता है कि रिक्यूजिजों तथा अन्य दूसरे विस्थापित जो वर्श 1972 से पूर्व एन0आई0टी0 ओल्ड फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में स्थित थे अब भी पुनर्स्थापना हेतु समस्या का कारण बने हुए हैं क्योंकि फरीदाबाद काम्पलैक्स प्र ाासन की भरपूर कोि ा ाों के बावजूद भी वे अपने पुराने स्थानों से उठकर नयी जगह पर जाने में हिचकिचा रहे हैं।

(ग) नहीं।

श्रीमती भारदा रानी : स्पीकर साहब मन्त्री जी ने पार्ट (ए) के जवाब में यह कहा है कि यह काम्पलैक्स इसलिये बनाया गया था कि फरीदाबाद में उचित, नियमित तथा योजित प्रकार का विकास हो सके। फरीदाबाद काम्पलैक्स का उसकी निर्धारित सीमा

के बाहर के क्षेत्र में कोई नियन्त्रण नहीं है। मैं लोकल बाडीज मन्त्री जी की बजाये मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगी.....

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : मन्त्री जी से ही पूछ लें, वह जवाब दे देंगे।

श्रीमती भारदा रानी : इन बाहर के क्षेत्रों का विकास और प्लानिंग कौन करता है ?

श्री ओम प्रका ा महाजन : स्पीकर साहब, वैसे तो इस सवाल का मेन सवाल से कोई संबंध नहीं है क्योंकि बाहर का क्षेत्र म्युनिस्पिल कमेटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम वहीं काम कर सकते हैं जहां पर हमें अधिकार है। वैसे तो हम काम कर रहे हैं और सरकार बिल्कुल ठीक ढ़ंग और ठीक प्रकार से जनहित में काम कर रही है।

श्रीमती भारदा रानीः सर, मन्त्री जी ने कहा है कि काम्पलैक्स के बाहर की जगह की बात है। काम्पलैक्स के बाहर की जगह के बारे में तो किसी ने पूछा ही नहीं है। वैसे यह बात ठीक है कि पुराने एन0आई0टी0 बगैरा का जो एरिया पड़ता है, उसकी रैगुलेट कम्पलैक्स करता है और उसके बाद जो एरिया आया है, उसका विकास हुड्डा कर रहा है। वहां पर जितना भी विकास हो रहा है, यह देखा गया है कि जब किसी जगह का विकास हो जाता है तो उस जमीन को एक्वायर करके उसके प्लाट्स बांट दिये जाते हैं। उसकी उचित तरीके से मेनटेनैंस नहीं हो रही है।

फरीदाबाद डिवैल्पमैंट अथोरिटी बना देने में क्या एतराज है, इससे वहां की जो लोकल समस्याएं हैं, वह तो कम से कम दूर हो जायेंगी। हुड्डा जो आजकल वहां पर प्लानिंग कर रहा है, वह उतना ध्यान नहीं दे पाता जितना देना चाहिये। अगर फरीदाबाद डिवैल्पमैंट अथोरिटी बना दी जाये तो इसमें सरकार को क्या आपति है ?

श्री अध्यक्ष : आप सवाल को बहुत लम्बा कर देती हैं जिससे सवाल समझने में दिक्कत आती है। आप क्वै चन ब्रीफ करें ताकि मन्त्री जी उसका जवाब दे सकें।

श्रीमती भाारदा रानी : वहां पर कायदे अनुसार सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को फरीदाबाद डिवैल्पमैंट अथोरिटी बनाने में कोई आपति नहीं होनी चाहिये, क्या ये बतायेंगे कि इनको आपति क्या है ?

श्री ओम प्रका ा महाजन : स्पीकर साहब, फरीदाबाद डिवैल्पमैंट अथोरिटी को बनाने का फैसला निगम कर सकात है और निगम बनाने पर विचार हो रहा है। इसके लिए 5 मैम्बरी एक कमेटी सितम्बर, 1985 में बनायी गयी थी। उसकी रिपोर्ट आने वाली है। जब उसकी रिपोर्ट आ जायेगी तो निगम बनाने के बाद इस बारे में विचार हो सकता है कि वहां पर फरीदाबाद डिवैल्पमैंट अथोरिटी बना दी जाये। एक बात मैं इस सदन की जानकारी और बहिन जी की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि यह काम्पलैक्स

हरियाणा के बाकी आम जिलों से अलग सा है। हमें इसको समझने के लिये इसकी बैकग्राउन्ड में जाना पड़ेगा। सन् 1947 में जब पाकिस्तान बना तो फरीदाबाद और बल्लभगढ़ दो टाउन होते थे। बल्लभगढ़ की आबादी केवल 7,000 और फरीदाबाद की आबादी केवल 5,000 थी। आज वहां पर आबादी लगभग सवा चार लाख के करीब हो चुकी है। इसका कारण यह है कि जो लोग पाकिस्तान से यहां विस्थापित बन कर आये थे, वे आकर बस गये। उनको काम देने के लिये सरकार ने वहां पर इंडस्ट्रीज खोल दीं। उन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिये कुछ कारीगर तो उत्तर प्रदे ा से आये, कुछ बाहर से आये और कुछ दिल्ली वगैरा से आये। इस तरह से 5 माडल टाउन्ज बन गये। वहां पर लोगों को बसाने के लिये 5 माडल टाउन्ज बनाये गये। एन0आई0टी0 1966 में इनको मिलाकर बनाया गया। फरीदाबाद की डिवैल्पमैंट करने के लिये एक प्लान 1971–72 में बनाया गया था जिसके तहत फरीदाबाद काम्पलैक्स एडमिनिस्ट्रे ान बनाने की योजना बनाई गई ताकि यह जो अनअथोराईज्ड कालोनीज बन रही हैं, ये न बनने पायें। आज जो स्थिति है, वह इस प्रकार है। इसके अन्दर 32 गांव हैं। 1972 के बाद इन 32 गांवों में से 5–6 गांवों में गैर मन्जूर भाुदा मकान लोगों ने बना लिये हैं। इसके अलावा 62 कलस्टर हैं। बड़ी मजबूरी में हमने इनका सुधार करने के लिये एक तरीका निकाला है। बहिन जी भी मेरे साथ उनका सुधार करने के लिये सहमत होंगी। इन कलस्टर्ज में से 36 कलस्टर तो एन0आई0टी0 में हैं, 11 बल्लभगढ़ में और 15 कलस्टर्ज ओल्ड फरीदाबाद में हैं।

इनमें से 16 कलस्टर्ज तो हम वहीं पर रखेंगे जिनमें से 2 क्लस्टर्ज ओल्ड फरीदाबाद में ही रखेंगे। इनमें बैठे लोगों को वहीं पर बैठे रहने देंगे। हमने सिर्फ ऐसे क्लस्टर्ज को उठाना है जो सड़क के किनारे, नाले के किनारे या रेलवे लाईन के किनारे बैठे हुए हैं। इस तरह से हमने कुल 46 क्लस्टर्ज उठाने हैं। हमने वहां पर 1624 ई0डब्ल्यू0एस0 के मकान बनाये हैं। इन 10 पार्कों में जो लोग बैठे हैं, उन्हें बसाया जाएगा और पार्क जनहित में खाली करवाए जायेंगे इन लोगों को बसाने के लिये इन मकानों की कीमत 12,000 रुपये रखी है। इस में एक कमरा, एक स्टोर और दूसरी सारी फैसिलिटीज हैं। 19 सालों में उन्होंने इन डबल स्टोरी मकानों की कीमत अदा करनी हे। इनके अलावा, 20,000 के करीब परिवार जो क्लस्टरों में बैठे हुए हैं, उनको भी साईट एण्ड सर्विस रूल्ज के तहत जमीन एक्वायर करके प्लाट काट कर दे रहे हैं। मैं सारे हाउस की जानकारी के लिये बता दूं कि 5 दिसम्बर को यानी थोड़े दिन पहले मैं बहिन जी के साथ उस तरफ गया था। इन्होंने जो जो काम चावला कालोनी, ऋशि कालोनी और साबुन वाली कालोनी वगैरा में बताये, वह सारे के सारे काम करवा दिये हैं। इसके अलावा बल्लभगढ़ में एक काफी बड़ा गंदा नाला है जो वहां के लोगों के लिये सिरदर्द बना हुआ था, वह नाला अभी सारा तो नहीं पर पौने दो किलोमीटर पक्का बनवा दिया गया है, उसकी सफाई करवा दी गई है। सैक्टर 23 में जिसके अन्दर बहिन जी का अपना मकान है, वहां हम ने इस साल दो पार्क नए बनवाए हैं। (व्यवधान व भाोर) मैं बहिन जी की जानकारी के लिये एक बात

और बता देना चाहता हूं कि ओल्ड फरीदाबाद के अन्दर 1976 में एक लाइब्रेरी–कम–आडीटोरियम बनाना चालू किया गया था, दुर्भाग्यव ा उसकी छत बैठ गयी थी, वहां के लोगों ने दिमागों में यह वहम डाल दिया कि वहां पर जिन्न–भूत होने की वजह से वह छत बैठी है। हमने उस आडिटोरियम की कंस्ट्रक ान का काम 1985 में फिर से भाुरू करवा दिया है जो 2–3 माह तक बनकर तैयार हो जाने की संभावना है।

श्री कंवल सिंह : स्पीकर साहब, अभी मन्त्री जी ने एक निगम की स्थापना के बारे में जिक्र किया था। मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि उस निगम की मोटी सी रूप रेखा क्या होगी, कितने एरिया में वह सर्व करेगा, कम से कम यह तो हाउस को बता दें।

श्री ओम प्रका ा महाजन : मैंने पहले ही कहा है कि एक 5 मैम्बरी कमेटी उसके लिये बनाई हुई है, उसकी रिपोर्ट अभी आने वाली है, वह जल्दी ही आ जायेगी। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि वह निगम क्या रूप–रेखा अख्तियार करेगा।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने काम्पलैक्स के बारे में सदन को बताया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपने साधनों को ध्यान में रखते हुए जनता की बहबूदी के लिये जितने भी काम हो सकते हैं, अच्छी तरह से करने

की कोि ा ा वह काम्पलैक्स एडमिनिस्ट्रे ान कर रहा है। मैं मन्त्री जी से एक बात कहना चाहूंगा कि भाहरों में झुग्गी–झोंपडियों के बहुत से इलाके हैं जो नालों के या रेलवे लाइनों के साथ–साथ या सड़कों के साथ–साथ लगते हैं। क्या मन्त्री जी उनको भी छोटे–छोटे प्लाट्स काट कर देना पसन्द करेंगे ? हमारे 20 सूत्री प्रोग्राम के अधीन लोगों को जितनी भी अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकती हैं, मिलनी चाहियें। मैं मन्त्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि यह काम जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी करने की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि लोगों को और ज्यादा तकलीफ न उठानी पड़े। क्या सरकार कोई ऐसी योजना पर विचार करेंगी ?

श्री ओम प्रका ा महाजन : स्पीकर साहब, बहुत तेज रफ्तार से इस विशय में पग उठा रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि कुछ ही महीनों में हमने 46 क्लस्टर उठाने हैं, वहां पर तो हम पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं लेकिन जो 16 क्लस्टर नहीं उठाने हैं, वहां हमने 31 लाख रुपया खर्च किया है। वहां सड़क बनाई हैं, मीठा पानी पीने के लिये दिया है और दूसरी सुविधाएं प्रदान की है लेकिन 46 क्लस्टर की जगह पर हम पैसा खर्च नहीं करना चाहते। पला गांव वाटर वर्क्स भाुरू करवा दिया है और एक दूसरे गांव लकड़पुर में भी पानी चालू करवा दिया है। स्पीकर साहब, इनकी भाास्त्री कालोनी है। इसकी गलियों का काम चालू

करवा दिया था भाायद वह पूरा कर दिया है। सैक्टर सात और पन्द्रह में सात नए पार्क बनवाए हैं।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : स्पीकर साहब, मेरा सवाल यह था कि बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उन इलाकों पर सरकार का पैसा खर्च हो रहा है जहां से उनको उठाना है। मेरा कहना यह है कि वहां पर पैसा खर्च न करके जल्दी ही उन लोगों को नई जगह पर बसा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : इस सवाल का जवाब दे दिया गया है।

चौधरी फूल चन्द : स्पीकर साहब, फरीदाबाद काम्पलैक्स के विकास के लिए सरकार बहुत कदम उठा रही है। अम्बाला भाहर की म्युनिसिपैल्टी बहुत पुरानी है। वहां पर पीने के पानी की समस्या है। परनी मिलता है लेकिन खराब है। सड़कों की हालत खराब है और गलियां और नालियां भी ठीक नहीं हैं। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि किसी योजना के अधीन वि ोश प्रकार की कोई ग्रान्ट देकर अम्बाला भाहर को भी विकसित करने का कोई प्रोग्राम है ?

श्री ओम प्रका ा महाजन : आनरेबल मैम्बर ने जो कुद कहा है वह बिल्कुल ठीक है। स्पीकर साहब, हरियाणा में 16 'ए' क्लास म्युनिसिपल कमेटीज हैं। लेकिन इनकी आर्थिक हालत ऐसी है कि बुहत सी कमेटीज डिवैल्पमैंट पर पैसा खर्च नहीं कर सकती क्योंकि उनके साधन कम हैं। इसी तरह से बी0 एण्ड सी0

म्युनिसिपल कमेटीज है जिनके साधन बहुत सीमित हैं और उनकी आमदनी बहुत कम है। ऐसी कमेटीज की हालत को कैसे सुधारा जाए, इस बारे में 18 तारीख को बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में मैं, गुप्ता जी, श्रीमती प्रसन्नी देवी जी और दूसरे अफसरान भाामिल हुए थे। मीटिंग में तय किया गया था कि जिन म्युनिसिपल कमेटीज की आमदनी कम है, हालत ठीक नहीं है, उनकी हालत सुधारने के लिए फण्डज दिए जाएंगे।

श्री ए0 सी0 चौधरी : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने बताया है कि फ रीदाबाद काम्पलैक्स का डिवैल्पमैंट बहुत अच्छे ढ़ंग से हो रहा है। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्शित करना चाहता हूं कि रेलवे लाइन के पर वाला एरिया ऐन0आई0टी0 फरीदाबाद काम्पलैक्स में है और जी0टी0 रोड के पार बल्लभगढ़ और फरीदाबाद भाहर भी काम्पलैक्स में हैं, लेकिन रेलवे लाइन और जी0टी0 रोड के बीच का हजारों एकड़ एरिया न तो काम्पलैक्स में है, न हुड्डा के अन्डर है और न ही कोई उस एरिया का वाली वारिस है। 1948 में जब जमीन ऐक्वायर हुई थी तो इसको भी ऐक्वायर कर लिया गया था लेकिन इस जमीन का कम्पनसे ान नहीं दिया गया और किसान कोर्ट में चले गए थे। स्पीकर साहब, वहां हालत यह है कि हजारों झुग्गियां बन गई है, लाखों ट्रक पावर हाउस की राख वहां डमप हो रही है। इस तरह से वह स्लम एरिया बनता जा रहा है। ऐसी हालत में अगर काम्पलैक्स एडमिनिस्ट्रे ान उस जगह को लुकआफटर न करे,

अनअथोराइज्ड पोजै ान को खत्म न करे और हुड्डा भी कुछ न करे तो वह एरिया स्लम बन जाएगा। फरीदाबाद की सारी सुन्दरता खत्म हो जाएगी। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या वहां फरीदाबाद डिवैल्पमैंट अथोरिटी जैसी कोई इंटेग्रेटिड बोडी बनाई जाएगी जो इंटेग्रेटिव–वे में काम करके फरीदाबाद इंडस्ट्रियल टाउन को स्लम एरिया होने से रोक सके ?

श्री ओम प्रका ा महाजन : स्पीकर साहब, जिस जमीन का यह जिक्र कर हरे हैं उस के बारे में रिहैब्लीटे ान डिपार्टमैंट हाईकोर्ट से हार गया और जमीन एंडिविजुअल के हाथ में आ गई। जब जमीन एंडिविजुअल के हाथ में आ गई तो उन्होंने आप काम करने वालों को और कबाड़ियों को वह जमीन बेच दी और उन लोगों ने वहां पर दुकानें बना ली। इस समय सुप्रीम कार्ट में केस चल रहा है। जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इसके साथ–साथ जितना इलाका है, उसको हम खूबसूरत बनाने के लिए कोि ा ा कर रहे हैं। दिल्ली मथुरा रोड पर हमने रास्ते में 330 सोडियम लाइट्स लगा दी है।

चौधरी साहब सिंह सैनी : स्पीकर साहब, मैं कुरूक्षेत्र के बारे में पूछना चाहता हूं। पिछले दिनों मन्त्री महोदय कुरूक्षेत्र गए थे और इन्होंने कुछ कालोनीज को देखा था लेकिन कुछ रह गई थी। मुख्य मन्त्री जी भी गए थे। स्पीकर साहब, कुरूक्षेत्र में ऐसी कालोनीज डिपैल्प हो गई हैं, जहां कोई फैसिलीटीज अवेलेबल

नहीं है। मैं मानता हूं कि वहां 'ए' क्लास कमेटी है लेकिन आमदनी कम है इसलिए कोई काम नहीं हो रहा है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर कोई वि ोश ग्रान्ट देकर गलियों, नालियों और सड़कों की मरम्मत आदि की फैसिलिटिज मुहैया की जाएंगी ?

श्री ओम प्रका ा महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि कुरूक्षेत्र के इलाके को भी कुछ मिलना चाहिये। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इनके पास पैसा है। इनके पास दो सौ दुकाने हैं लेकिन उनका किराया किसी का पच्चीस रुपया है, किसी का चालीस रुपया है और किसी का पचास रुपया है। हमने सात आदमियों की एक कमेटी बना दी है और उस कमेटी के चेयरमैन डी0सी0 हैं। एक फैसला लिया गया है कि जिन दुकानों का किराया नाम मात्र है, उनको बेच दिया जाए और उनकी जगह नई दुकानें बना दी जाएं। इसी मार्च से पहले उन दुकानों को बेच देने की संभावना है। इनके बेचने से लाखों रुपया आएगा और इस रुपये से इतनी ही नई दुकानें और बन जायेंगी। इस तरह से माहवार आमदनी बहुत ही ज्यादा बढ़ जायेगी पैसा इक्ट्ठा होने से डिवैल्पमैंट भी हो जायेगा। मैं पिछले दिनों कुरूक्षेत्र गया था। डी0सी0 और प्र ाासक मेरे साथ थे। उस दिन बरसात हो रही थी। बरसात में हम लोग गलियों में घूमते रहे। इन्होंने जितने काम कहे थे, वे पूरे हो गए हैं और कोई काम बाकी नहीं रहा।

श्री नेकी राम : स्पीकर साहब, मेरा हल्का रतिया है। रतिया भाहर की म्युनिसिपल कमेटी घग्गर पर है और दूसरी तरफ नहर है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर भी कुछ डिवैल्पमैंट का काम किया जाएगा ?

श्री ओम प्रका ा महाजन : स्पीकर साहब, दो बार रतिया जाने का प्रोग्राम बनाया लेकिन किसी कारण से वह पोस्टपोन करना पड़ा है। मैं आदरणीय मैम्बर से मिलकर रतिया का प्रोग्राम बना लूंगा और जो भी समस्या होगी उसको हल कर दिया जाएगा।

बहिन भाान्ति देवी : अध्यक्ष महोदय, करनाल एक पुराना ऐतिहासिक भाहर है। वहां पर कई गन्दे नाले बहते हैं। मन्त्री जी को मैंने इस स्थिति का निरीक्षण भी करवाया था लेकिन उन में किसी एक नाले की भी अभी तक मुरम्मत नहीं की गयी है। न ही उन नालों को पक्का करवाया गया है न ही उन को ढकवाया गया है। वे नाले बह बह कर चौड़े हो गये हैं, उनमें बदबू मारती है। बीमारियां फैलने का भी खतारा है। ऐसा न होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से जो अरबन ऐस्टेट्स में नई बस्तियां बनी हैं उनका सीवरेजत सिस्टम भी बहुत खराब है। वह कुछ सिस्टम इस तरह का है कि जब पानी का बहाव ज्यादा होता है तो वहां कालोनीज में पानी खड़ा हो जाता है। सिस्टम बड़ा ही डिफैक्टिव है। क्या मिनिस्टर

साहब मुझे इस बात का अव वासन देंगे कि करनाल भाहर की इन तकलीफों को जल्दी ही दूर करवाया जाएगा ?

श्री ओम प्रका ा महाजन : अध्यक्ष महोदय, बहिन जी ने दो सवाल पूछे हैं। पहला सवाल नालों से संबंधित है। वहां एक रामनगर नाला है। वह नाला लगभग साढ़े चार किलोमीटर लम्बा है और 75 परसैन्ट पानी इस नाले के द्वारा जाता है इस पर लगभग 38 लाख रुपये की लागत कवर करने पर आयेगी। इस बारे में हमने पब्लिक हैल्थ विभाग से इसको कवर करने की बात की थी। बहिन जी को, अध्यक्ष महोदय, याद होगा एक दिन हम पैदल चल कर इस के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचे थे और सारा निरीक्षण भी किया था कि इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। इसका आधा काम तो हो चुका है। जहां तक इनकी दूसरी बात का संबंध है कि वीवरेज सिस्टम डिफैक्टिव है। पहले जब बरसात आती थी तो वहां पर एक–एक दो–दो फुट पानी भर जाता था लेकिन अब हमने उसको ठीक करवा दिया है, और कनैक ानज भी दिये हैं। अब चाहे कितनी भी जारों से बरसात आये, वहां पर एक बूंद पानी भी नहीं रूकेगा।

सेठ राम दास धमीजा : अध्यक्ष महोदय, अम्बाला कैन्ट एक 'ए' क्लास म्युनिसिपल कमेटी है, आमदनी भी बहुत है वहां पर काम भी बहुत हुए हैं और अभी और बहुत से काम बाकी भी रह रहे हैं। वहां पर 64 के लगभग अनअथोराईज्ड कालोनीज हैं। अगर सरकार की तरफ से म्युनिसिपल कमेटी को और ग्रान्ट दी

जाएगी तो उस इलाके की बड़ी भाानदार डिवैल्पमैंट हो सकेगी। इसी तरह से तीन चार कालोनीज जैसे ढेर कालोनी, बाजीगर कालोनी और बाल्मीकी कालोनी। ये पिछले 50–100 सालों से युंही अन–अथोराईज्ड ही पड़ी हुई हैं, न ही इनकी कोई डिवैल्पमैंट हो सकी है और न ही सरकार को यहां से कोई आमदनी ही होती है। अगर सरकार इन कालोनीज को अथोराईज कर दे तो सरकार को टैक्स वगैरह की यहां से काफी आमदनी हो सकती है। मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा कोई विचार सरकार का है जिससे कि इन सभी कालोनीज को आथोराईज किया जा सके। मेरे विचार से यहां पर जो कच्चे पक्के नाले हैं उनको अगर पूरी तरह से पक्का करवा दिया जाएगा तो इस तरह की कई प्रोबलम्ज इन कालोनीज की हल हो जाएंगी। ड्रेनेज सिस्टम भी सही हो जाएगा।

श्री ओम प्रका ा महाजन : अध्यक्ष महोदय, जहां तक नालों को पक्का करवाने की बात का संबंध है अभी पिछले 15 रोज पहले, इनके साथ बैठकर वहां के एडमिनिस्ट्रेटर से बातें की गयीं थी और पब्लिक हैल्थ के एक्सीअन को भी बुलाया गया थ। वे इस तरह के प्लान तैयार करवा रहे हैं। जैसे ही वे प्लान्ज तैयार हो जाएंगे, यह काम भी हो जाएंगे। दूसरी बात ग्रान्ट्स के संबंध में है। हमारी जितनी म्युनिसिपल कमेटियां हैं, उनमें से सब से अच्छी 'ए' क्लास कमेटी इनकी हैं और इनके पास पैसा भी बहुत है। फिर भी ये ग्रान्ट की मांग करें तो ठीक नहीं।

चौधरी दिलू राम बाजीगर : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्का चीका गुल्लाह में 1982 में एक म्युनिसिपल कमेटी बनायी गयी थी लेकिन वहां के लोगों ने उसका नाम मु कल कमेटी रखा हुआ है क्योंकि लोगों को उस म्युनिसिपल कमेटी का कोई फायदा नहीं हो रहा है। उस म्युनिसिपल कमेटी में नये गांव भी हैं और आपको पता भी है कि गांवों का वतावरण ऐसा है कि वहां डंगरों के बांधने, भूसे के लिये, रसोई के लिये अलग और रहने के लिये अलग–अलग जगहें होती हैं और अगर सरकार म्युनिसिपल कमेटी टैक्स लगाती है तो सभी पर लगता है लेकिन जमींदारों को उस कमेटी का कोई लाभ नहीं है। पिछली बार जब पार्लियामैंट का इलैक ान हुआ था तो मैंने लोगों को आ वासन दिलवाया था कि आपकी सारी मु कलों को दूर किया जाएगा और हर तरह की सहूलियतें आप लोगों को म्युनिसिपल कमेटी से दिलवाई जाएंगी या फिर आपके गांव को म्युनिसिपल कमेटी से निकलवाया जाएगा या फिर म्युनिसिपल कमेटी को खत्म करवा दिया जाएगा। इसके साथ–साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि 1982 में जो कर्मचारी भर्ती हुए थे, वह अब तक पक्के नहीं हुए हैं। पता नहीं क्या कारण है, उनको आधी–पे मिलती है। इससे अगला प्र न मेरा यह है कि वहां पर एक सेक्रेटरी ने 12–13 दुकाने बनायीं और उसने लोगों से यह कहा कि ये दुकानें आपको दे देंगे। बयाने के तौर पर लोगों से पांच–पांच हजार रुपया लिया और पांच–पांच, छः–छः हजार रुपया घपले के तौर पर लिया गया। इस बारे में मैंने मन्त्री जी और डायरैक्टर साहब को भी लिखा कि

इसकी जांच की जाए इस के लिये एक अधिकारी मौके पर गये, उन्होंने जांच की और वे कर्मचारी दोशी पाए गए लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई इस बारे में मैं मन्त्री महोदय को मिला था और उन्होंने मुझे बताया था कि मैं उस आदमी को ससपैन्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसके बारे में मुझे किसी दूसरे मन्त्री जी ने कहा है। इस तरह से 80–90 हजार रुपये यह आदमी खा गया लेकिन आ चर्य की बात है कि आज तक इस के खिलाफ कोई एक ान नहीं लिया गया है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से यह कहूंगा कि इन सभी बातों की जांच करवायी जाए और इस मु कल कमेटी के काम काज को ठीक करवाया जाए।

श्री अध्यक्ष : अधिकारी का नाम रिकार्ड न किया जाए।

श्री ओम प्रका ा महाजन : अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद की बात है कि एक आनरेबल मैम्बर ने इस प्रकार की छोटी सी बात कही है जो बिल्कुल बेबुनियाद है, तर्कसंगत नहीं है। अगर वहां की जनता यह चाहेगी कि वहां की म्युनिसिपल कमेटी न रहे तो हमें क्या एतराज हो सकता है, हम खत्म करवा देंगे। दूसरी बात इन्होंने यह कही कि किसी पर कोई एक ान नहीं लिया गया है, ऐसी बात नहीं है। जांच के अनुसार हम ऐक ान ले रहे हैं। कहीं पर भी किसी को बख्शा नहीं जाएगा।

प्र न देने वाले सदस्यों को बजाये अन्य सदस्यों द्वारा प्र न पूछने की अनुमति देना

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक अर्ज करना चाहूंगा कि अपोजी ान के मैम्बर्ज तो यहां हैं नहीं और आप बड़े ही लिबरल हो रहे हैं। सप्लीमैंटरी पूछने की सभी को खुल कर आज्ञा दे रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अपोजी ान के भाईयों ने जो सवाल पूछ रखे हैं, अगर उन पर भी सप्लीमैंटरी पूछ लिये जाएं और हमारे इधर के साथी उन सवालों के बारे में पूछ लें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं होगी। हमारे अधिकारियों तथा मन्त्रियों ने सवालों से संबंधित जानकारी इक्ट्ठी करने में बड़ी मेहनत की है। अगर उन सवालों पर भी डिस्क ान अलाऊ कर दे ंतो बेहतर रहेगा ताकि हमारी सारी बातें हरियाणा की जनता के सामने आ सकें और जनता सरकार की कारगुजारी से अवगत हो सके।

Mr. Speaker : I agree as per the Rules of Procedure.

तारांकित प्र न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री बृज मोहन : अध्यक्ष महोदय, भाहरों में वाटर सप्लाई और सीवरेज का काम अलग–अलग डिपार्टमैंट्स करते हैं। कुछ काम लोकल सेल्फ गवर्नमैंट डिपार्टमैंट करता है और कुछ काम पब्लिक हैल्थ वाले करते हैं लेकिन काम के लिये जिम्मेवारी कोई विभाग अपने ऊपर नहीं उठाता। अगर पब्लिक हैल्थ वालों के पास जाएं तो वे कह देते हैं कि यह काम हमारा नहीं है, लोकल सैल्फ डिपाटैमैंट वालों का है और अगर इनके पास जाते हैं तो ये कह देते हैं कि यह काम पब्लिक हैल्थ वालों का है। अतः मेरी

सरकार से रिकवैस्ट है कि ऐसे कामों के लिये किसी न किसी विभाग की जिम्मेवारी अव य फिक्स की जानी चाहिये ताकि लोगों को काम करवाते वक्त इस प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

10.00 बजे

श्री ओम प्रका ा महाजन : अध्यक्ष महोदय, एक कमेटी परसों ही बनाई गई है। यह बिल्कुल ठीक है कि पब्लिक हैल्थ विभाग और नगरपालिकाओं में थोड़ा सा तालमेल कम था। अब एक कमेटी बना दी गई है। अब इन दोनों की कोई भी स्कीम होगी उसके एस्टीमेट्स यह कमेटी पास करेगी। पानी के बारे में एक दस करोड़ रुपये की स्कीम ऐसी है जो बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा समय और लगेगा और इनकी जो मु कलात है वह कुछ समय में दूर हो जाएगी।

श्री मती भाारदा रानी : स्पीकर साहब, यह कोई जरूरी नहीं कि जहां पर कार्पोरे ान हो वहीं पर डिवैल्पमैंट अथोरिटी बने। फरीदाबाद में कार्पोरे ान बनने से पहले वहां पर डिवैल्पमैंट अथारिटी बनाने में क्या हर्ज है क्योंकि वहां पर बहुत तेजी से हैफैजर्ड ग्रोथ हो रही है इसलिये वहां पर डिवैल्पमैंट अथारिटी बनाने पर जरूर विचार किया जाना चाहिए।

श्री ओम प्रका ा महाजन : बहिन जी अपनी तरफ से एक नोट भिजवा दे ंहम उसे एग्जामिन करवा लेंगे।

Teacher/Masters appointed in Mohindergarh District

***1074. Shri Nihal Singh :** Will the Minister of State of Education be pleased to state-

(a) the total number of J.B.T. teachers, Social Studies masters having B.Ed. or M.Ed., qualification, Science and Mathematics Masters and O.T. teacher's appointed in Mohindergarh district since 1st April, 1985, to-date; and

(b) the category-wise number of teachers/masters out of those as referred to in part (a) above, belonging to districts other than Mohindergarh ?

Minister of State for Education (Shri Jagdish Nehra) :

(a) the total number of different categories of teachers/masters appointed in Mohindergarh district since 1-4-85 is as below-

1. J.B.T. Teachers	63	
2. S.S. Masters/Mistresses		67
3. Science Masters/Mistresses	52	
4. Math. Masters/Mistresses		19
5. O.T. Teachers		59
Total		**260**

(b) The category-wise number of teachers/masters out of those referred to in part (a) above belonging to districts other than Mohindergarh is as under

1. J.B.T. Teachers	2
2. O.T. Teachers	1
Total	**3**

श्री भले राम : स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने महेन्द्रगढ़ के स्कूलों में 1–4–85 से लगाए गए अलग–अलग कैटेगरी के टीचर्ज की संख्या 260 बताई है। मैं जानना चाहता हूं कि महेन्द्रगढ़ जिले में प्राइमरी से मैट्रिक तक जितने स्कूल हैं क्या उन सब में अध्यापकों की संख्या पूरी है ?

श्री जगदी ा नेहरा : इस साल में संख्या करीब–करीब पूरी थी। जो प्राइमरी स्कूल है उनमें टीचर्ज की रे ाो 1 : 45 की है। टोटल महेन्द्रगढ़ जिले में स्थिति करीब–करीब ठीक है।

श्री नेकी राम : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल तो टीचर्ज के बारे में है लेकिन मैं थोड़ा सा आगे पूछना चाहता हूं। मैं खास कर सदन के नेता से जानना चाहूंगा और आ वासन चाहूंगा कि रतिया हल्के में कालेज की बड़ी मांग है क्या उसको पूरा किया जाएगा ? इस हल्के से सिरसा और हिसार दूर पड़ते हैं करीब 100 किलोमीटर दूर कालेज पड़ते हैं और गरीब बच्चे इतनी दूर जा नहीं सकते। क्या मन्त्री महोदय वहां कालेज स्थापित करने के लिए कार्यवाही करेंगे ?

श्री जगदी ा नेहरा : अध्यक्ष महोदय, यदि वहां के एरिया की मांग होगी और वहां पर इतने हाई स्कूल होंगे कि

कालेज खोलना वाएबल होगा तो उस बारे में सरकार कंसिडर कर सकती है।

चौधरी फूल चन्द : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री जी ने प्राइमरी स्कूलों में 45 बच्चों के पीछे एक मास्टर की रे ाो बताई है। क्या मन्त्री जी के नोटिस में यह बात है कि कई प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या दो–दो सौ और अढ़ाई–अढ़ाई सौ है लेकिन वहां पर टीचर केवल एक ही है। क्या इस तरह का सर्वे करवाएंगे और प्राइमरी स्कूलों में जो टीचर्ज की कमी है, उसको कब तक पूरा करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगदी ा नेहरा : स्पीकर साहब, हरियाणा में आल फुल फलैज्ड प्राइमरी स्कूल में कहीं भी एक टीचर नहीं है। वर्श 1983–84 में कुछ स्कूलों में एक–एक टीचर जरूर था लेकिन 1984–85 में हमने सभी 550 स्कूलों में डबल मास्टर्ज कर दिए। आज कोई भी ऐसा प्राइमरी स्कूल नहीं जहां पर सिंगल टीचर हो। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ स्कूलों ममें टीचर्ज की कमी है, वह हमें बता दे ंहम उन जगहों को देख लेंगे। जे0बी0टी0 टीचर्ज की संख्या आम तौर पर बच्चों के मुताबिक करीब–करीब ठीक है।

चौधरी फूल चन्द : स्पीकर साहब, भाायद मन्त्री महोदय को गलत आंकड़े दिए गए हैं। मैं कई स्कूलों के नाम इनको अभी बता देता हूं जिनमें टीचर्ज की संख्या कम है।

श्री अध्यक्ष : आप इनको अलग से मिल कर उनकी लिस्ट दे देना।

चौधरी साहब सिंह सैनी : स्पीकर साहब, आपकी इजाजत से मैं क्वै चन के स्कोप से थोड़ा सा बाहर बोलूंगा। मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि कई सब्जैक्ट्स ऐसे हैं जिनके मास्टर स्कूलों में नहीं हैं। जैसे किसी स्कूल में बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहते हैं लेकिन वहां पर संस्कृत का मास्टर नहीं है उसकी बजाए पंजाबी मास्टर की पोस्ट है। जहां पर बच्चे पंजाबी पढ़ना चाहते हैं वहां संस्कृत मास्टर की पोस्ट है। राम सिंह जी के हल्के मंगोली जाटान में 550 बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहते हैं लेकिन वहां पर कोई संस्कृत टीचर नहीं है। इसी प्रकार से मेरे हल्के में दो स्कूल हैं उनमें कुछ बच्चे पंजाबी पढ़ना चाहते हैं, वहां पंजाबी मास्टर की पोस्ट नहीं है। क्या मन्त्री जी ऐसा इन्तजाम करेंगे कि बच्चे जिस सब्जैक्ट को पढ़ना चाहें, उस प्रकार से टीचर्ज लगाएंगे। अगर हम डी0ई0ओ0 से पूछते हैं तो वे कह देते हैं कि पोस्ट सैंक ांड नहीं है।

श्री जगदी ा नेहरा : जिस स्कूल से मांग आती है कि हमने पंजाबी पढ़नी है या संस्कृत पढ़नी है, आम तौर पर हम वहां ऐसे टीचर लगा देते हैं। जिन स्कूलों के बारे में इन्होंने बताया है, अगर उनकी मांग आएगी तो हम वहां पोस्टें सैक ान कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : ये कहते हैं कि मांग तो है लगा कब तक देंगे ?

श्री जगदी ा नेहरा : यदि मांग है तो हम इस सै ान में जो अप्रैल में भाुरू होगा वहां टीचर्ज लगा देंगे। मई जून तक हम टीचर्ज जरूर भेज देंगे।

चौधरी हुक्म सिंह : स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगां कि हमारे रोहतक जिले में पिछले साल जे0बी0टी0 टीचर्ज बहुत सरप्लस थे। मेरा हल्का टेल पर है और महेन्द्रगढ़ के साथ लगता है। मैं जानना चाहता हूं कि जो सरप्लस टीचर्ज हैं उनको देहातों के स्कूलों में लगाया जाएगा क्योंकि देहातों में टीचर्ज की संख्या कम है ?

श्री जगदी ा नेहरा : अध्यक्ष महोदय, पिछले से पिछले साल सरकार को यह ि ाकायत आई कि भाहरों में मास्टर अधिक हैं और बच्चे कम हैं लेकिन गांवों में ऐसा नहीं है। इसलिये पिछले साल हमने इसको रै ानेलाइज किया। जहां सरप्लस स्टाफ था उनको दूर भेज दिया है। अब भाहरों में सरप्लस स्टाफ नहीं है।

चौधरी अजमत खां : स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने कहा कि अब जे0बी0टी0 टीचर्ज करीब–करीब पूरे हैं। फरीदाबाद जिले में तो जे0बी0टी0 टीचर्ज की बात ठीक है वहां पर 1:30 की रे ाो है लेकिन हथीन के इलाके में रे ाो 1:70 के करीब पहुंच गई है। आज हर टीचर कहीं न कहीं से जोर लगवा कर भाहर के नजदीक

पहुंचने की कोि ा ा करता है। जब तक टीचर्ज को रूरल अलाउंस नहीं मिलेगा, तब तक देहातों की यह समस्या खत्म नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि देहात के टीचर्ज को रूरल अलाउंस दिया जाए।

श्री जगदी ा नेहरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात बिल्कुल दुरूस्त है। जो अध्यापक वर्ग है, उसकी मांग भी थी कि उनको रूरल अलाउंस दिया जाए। जिस तरह से अध्यापकों को भाहरी अलाउंस दिया जाता है उसी तरह से रूरल अलाउंस भी दिया जाए। यह केवल एजूके ान डिपार्टमैंट की ही बात नहीं है बल्कि यह सारे डिपार्टमैंट की बात है। यह पालिसी मैटर है इसलिए इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जहां तक रै ानेलाइजे ान की बात है उसमें ि ाक्षा विभाग पूरी तरह से सजग है। जिस जगह पर स्टाफ की कमी थी, वहां पर स्टाफ भेज दिया है। यह बात भी दुरूस्त है कि जिस प्राइमरी स्कूल में 60–70 बच्चे हैं वहां पर भी एक टीचर है और जिस प्राइमरी स्कूल ममें 80–90 बच्चे हैं वहां पर भी एक टीचर है। यह बात भी ठीक है कि जिस प्राइमरी स्कूल में ज्यादा बच्चे हो जाएं वहां पर एडी ानल स्टाफ भेजा जाए। यह नहीं होना चाहिए कि जिस प्राइमरी स्कूल में 30–40 बच्चे हैं उसमें भी एक टीचर हो और जिस स्कूल में 60–70 बच्चे हैं वहां पर भी एक टीचर हो। मैं बताना चाहूंगा कि ि ाक्षा विभाग इस बात के लिए कोि ा ा

करता है कि जिस प्राइमरी स्कूल में रे ाो के हिसाब से ज्यादा बच्चे हो जाएं, उस स्कूल में एडी ानल स्टाफ लगाया जाए।

चौधरी सूबे सिंह पुनिया : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाशण में दो लड़कियों के कालेज खोलने के बारे में बताया है। इनमें से एक कालेज फरीदाबाद में और एक कालेज देहात में खोला जाएगा। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि कालेज खोलने का क्या क्राइटेरिया है। इसके अलावा एक बात मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जिन इलाकों में पिछले 5–6 साल से ट्रेनिंग की क्लासिज नहीं है क्या उन इलाकों में ट्रेनिंग क्लासिज का प्रावधान किया जाएगा।

श्री जगदी ा नेहरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाशण में दो गर्ल्ज कालेज खोलने के बारे में जिकर किया है उन कालेजों को खोलने का क्या क्राइटेरिया है। मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि एक गर्ल्ज कालेज फरीदाबाद में खोला जाएगा और एक देहात में खोला जाएगा और कालेज खोलने का यह क्राइटेरिया है जहां पर कालेज खोलना हो उसके नजदीक दूसरा कोई कालेज न हो, हाई स्कूल भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में नजदीक हों और बच्चों की तादाद भी ज्यादा हो, उस जगह पर कालेज खोला जाएगा।

Recruitment made in the Intensive Cattle Development Project Cantres

***1072 Shri Dharam Bir Gauba :** Will the Minister of State for Animal Husbandry be pleased to state-

(a) total number of class IV employees recruited on daily wages during the period from 1-1-1985 to-date in Intensive Cattle Development Project Centres in the State;

(b) whether the employees as referred to in part (a) above have been recruited through Employment Exchanges or through other modes; and

(c) the number of employees out of those referred to in part (a) above, belonging to the Naraingarh Constituency ?

श्री अध्यक्ष : इस क्वै चन के लिए गवर्नमैंट ने एक्सटैं ान मांगी है। वह मैंने दे दी है। मन्त्री जी से आया पत्र इस प्रकार है—

Interim Reply

"D.O. No. 1379-AH(V)-86/3455

Minister of State for Animal Husbandry, Haryana

Chandigarh:

SH. LAL SINGH Dated :- February 19, 1986

Subject:- Starred Assembly Question No. 1072 regarding recruitment made in Intensive Cattle Development Project Centres.

Dear Sardar Sahib,

Kindly refer to the above mentioned Starred Assembly Q. No. 1072 asked by Shri Dharam Bir Gauba, M.L.A., during the ensuing session of Vidhan Sabha. This question has been fixed for 20th February, 1986. The information asked for is not roadily available and has to be collected from the field. Efforts are being made to collect this information at the earliest. In the circumstances it will not be possible for the Government to answer this question on 20-2-1986. As the collection of the desired information is likely to take some time, I shall be grateful if the Government is given two weeks extension for answering this question.

With regards,

Yours Sincerely,

Sd/-

(LAL SINGH)

S. Tara Singh

Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh"

Veterinary Hospitals and Dispensaries in the State

***1057 Shri Ram Bilas Sharma:** Will the Minister of State for Animal Husbandry be pleased to state-

(a) the total number of veterinary hospitals, dispensaries and centres at present in the State-

(b) the number of posts of veterinary Doctors, Dispensers, Stock Assistants and Assistants lying vacant in the aforesaid veterinary hospitals, dispensaries and centres; and

(c) whether there is any proposal under the consideration of the Government to fill up the posts referred to in part (b) above together the time by which these are likely to be filled up ?

प ुपालन राज्य मन्त्री (चौधरी लाल सिंह) :

(क) (i) प ु हस्पतालों की कुल संख्या

376

(ii) प ु औशधालयों की कुल संख्या

336

(iii) कृत्रिम गर्भादान व स्टाकमैन सैन्टर की कुल संख्या892

(ख) (i) प ु चिकित्सक के रिक्त पद

61

(ii) प ु औशधक के रिक्त पद

62

(iii) प ुधान सहायक के रिक्त पद

40

(iv) प ुधान सहायकों के रिक्त पद

भून्य

(ग) इस समय सरकार ने रिक्त पदों को भरने पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। अतः सरकार द्वारा जब प्रतिबन्ध हटाया जायेगा तब ये रिक्त पद नियमानुसार भरे जायेंगे।

श्री भले राम : स्पीकर साहब, चौधरी लाल सिंह जी ने बड़े आराम से आंकड़े दिए हैं और बहुत काबिल मिनिस्टर हैं। मैं आपके द्वारा इनसे जानना चाहूंगा कि जो 892 आर्टीफि ियल इनसेमीने ान सैन्टर्ज और स्टोकमैन सैन्टर्ज बताए हैं, ये कौन–कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं और इनका क्या फंक ान है ?

चौधरी लाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैन सवाल में यह नहीं पूछा गया कि ये सैन्टर्ज कहां–कहां पर हैं। माननीय सदस्य इस बारे में लिख कर मेरे पास भेज दें या मेरे कमरे में आ जाएं मैं इनको इस बारे में सक कुछ बता दूंगा।

चौधरी साहब सिंह सैनी : स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने सवाल के भाग (ख) का जवाब दिया है कि प ु चिकित्सक के 61, प ु औशधक के 62 और प ुधन सहायक के 40 पद खाली पड़े हैं। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि ये पद

कब से खाली हैं और इनको भरने के लिये कोई प्रयत्न किए गए हैं या नहीं ?

चौधरी लाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये पद काफी दिनों से खाली पड़े हैं। जब से डाक्टरों की कमी हुई है तब से खाली पड़े हैं।

चौधरी हुक्म सिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने सवाल के भाग (क) के जवाब में बताया है कि प ा हस्पतालों की कुल संख्या 376 है और प ा औशधालयों की कुल संख्या 336 है। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इनमें से भाहरों में कितने हैं और देहातों में कितने हैं ? इस के अलावा, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि 1985–86 में कितने प ा हस्पताल बनाए गए और कितने प ा औशधालय बनाए गए।

चौधरी लाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेन सवाल में इस बारे में पूछा ही नहीं। ये मेरे कमरे में आ जाएं, मैं इनको बता दूंगा।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं पोजी ान क्लीयर कर देता हूं। हम इसी साल मार्च तक 40 प ा औशधालय और 30 प ा हस्पताल खोलेंगे। इस साल यानी 1985–86 में जोकि मार्च में खत्म होगा 40 प ा औशधालय और 30 प ा हस्पताल खोलेंगे। इस साल हमने प ाधन की भलाई के लिए 12 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और अगले साल 13 करोड़

रुपए खर्च करने का फैसला किया है ताकि प ाुओं की ठीक देखभाल हो सके और ज्यादा से ज्यादा प ा हस्पताल और प ा औशधालय खोले जो सकें।

चौधरी धर्मबीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने सवाल के (सी) भाग के जवाब में कहा है :

"At present there is ban on filling up of vacant posts. Posts will be filled up under rules as and when the ban is lifted by the Government".

मैं जानना चाहूंगा कि अब ये पोस्टें सवाल रूल भरी जाएंगी या नहीं और पहले जो रिक्रूटमैंट की गई थी, वह अंडर रूल की गई है या नहीं?

चौधरी लाल सिंह : स्पीकर साहब, सवाल का जवाब हिन्दी में दिया हुआ है लेकिन माननीय सदस्य सप्लीमैंटरी इंगलि ा में पूछ रहे हैं। मैंने भी सवाल का जवाब हिन्दी में पढ़ा है, इनको हिन्दी में सवाल पूछना चाहिए।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं बता देता हूं। माननीय सदस्य ने पूछा है कि जो स्टाफ भरा गया है क्या वह नियमानुसार भरा गया है। जो भी भर्ती की जाती है वह बाकायदा नियमानुसार की जाती है। यह हो सकता है कि कहीं पर कोई डेलीवेजिज पर या एडहाक पर कोई पोस्ट भर ली गई हो वह भी कोई फोर्थ क्लास की पोस्ट भरी गई होगी। जो भी

भर्ती की गई है वह बाकायदा कायदे कानून के हिसाब से भरी गई है। जो प ा चिकित्सक के 61 पद खाली हैं ये 5141 पदों में से खाली हैं और ये बहुत ज्यादा दिनों से खाली नहीं है जो इन पदों पर भर्ती की हुई है वह कायदे कानून के हिसाब से की हुई है। जब कोई पोस्ट भरनी जरूरी हो, तो उसके लिए बैन लिफ्ट भी करते हैं। पोस्टों पर बैन इसलिए लगाया गया था ताकि सरकार के खर्चे कम हों लेकिन जहां स्टाफ की जरूरत हो वहां दूसरी जगह से भी स्टाफ भेजते हैं, एडजस्टमैंट करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से हस्पतालों में डाक्टर्ज फालतू हैं इसलिये उनको दूसरे हस्पतालों में भी भेज दिया जाता है। पोस्टों पर बैन इसलिए भी लगाया हुआ है ताकि एक जगह से दूसरी जगह पर स्टाफ की एडजस्टमैंट की जा सके और सरकार का खर्चा कम हो सके। प ा औशधक के 706 पोस्टों में से 62 पद खाली हैं प ाधन सहायक के 1710 पदों में से 40 पद खाली हैं, कोई ज्यादा पोस्टें खाली नहीं हैं। यदि इन पदों को भरने की जरूरत हुई तो हम इनको भरने की कोि ा ा करेंगे।

श्री निर्मल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने प ा हस्पतालों की कुल संख्या 376, प ा औशधालयों की कुल संख्या 336 तथा कृत्रिम गर्भादान व स्टाकमैन सैन्टरों की कुल संख्या 892 बताई है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इनके मन्त्री बनने के बाद कितने नए हस्पताल खुले हैं और कितने पुराने थे ? दूसरे इनके मन्त्री बनने के बाद कितने हस्पताल अकेले

नारायणगढ़ क्षेत्र में खोले गए हैं ? इसके साथ–साथ इन्होंने यह भी बताया है कि कुछ रिक्त पद सरकार द्वारा बैन लगाये जाने के कारण नहीं भरे गए। इस बारे में मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इनके मन्त्री बनने के बाद नारायणगढ़ में कितने रिक्त पदों को भरा गया और दूसरी जगह कितने पदों को भरा गया ?

चौधरी लाल सिंह : नारायणगढ़ भी इसी प्रदे ा और दे ा का हिस्सा है। वहां पर हस्पताल खोला जाना कोई गलत बात नहीं है। जहां पर जितनी जरूरत हस्पताल खोले जाने की होती है उसी हिसाब से सरकार हस्पताल खोलती है। जो सवाल इन्होंने पूछा है उसके लिये अलग से नोटिस दे दें, जवाब दे दिया जायेगा।

श्री निर्मल सिंह : स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब तो आया नहीं (ाोर)

श्री अध्यक्ष : आप इन्हें मिल कर इस बारे में पूरी इन्फर्मे ान ले लें।

चौधरी सुरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, एक सवाल श्री हुक्त सिंह जी ने पूछा था और दूसरा सवाल श्री निर्मल सिंह जी ने पूछा था। इन दोनों सवालों का मन्त्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब ये कहते हैं कि लिख कर दे दें, जवाब दे दिया जायेगा (विध्न) मेरा भी एक सवाल है and I want to seek some information.

Mr. Speaker : What information do you want? (Interruptions.)

चौधरी लाल सिंह : सर, मैं इसका जवाब दे देता हूं। (ाोर)

श्री अध्यक्ष : आप सवाल को दोहरा दीजिए।

चौधरी सुरेन्द्र सिंह : मेरा सवाल यह है कि इन्होंने इस प्र न के उत्तर में बताया है कि प I हस्पतालों की कुल संख्या 376 है, प I औशधालयों की कुल संख्या 336 है और कृत्रिम गर्भाधान व स्टाकमैन सैन्टरों की कुल संख्या 892 है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इनमें से देहात में कितने हस्पताल व सैन्टर हैं और भाहरों में कितने हैं ? हम यह नहीं कहते कि नारायणगढ़ में हस्पताल क्यों खोले गए। नारायणगढ़ बैकवर्ड इलाका है, वहां पर हस्पताल खुलने चाहिएं। इनको इस बारे में बात देना चाहिए कि इनके मन्त्री बनने के बाद वहां पर कितने हस्पताल खोले गए हैं ?

चौधरी लाल सिंहः .....

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः .....

श्री अध्यक्ष : जो बातें इन्होंने कहीं है, वह रिकार्ड पर न लाई जायें।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, जो सवाल इन्होंने पूछा है उसका जवाब मैं दे देता हूं। इन्होंने पूछा है कि भाहरों में कितने हस्पताल और देहात में कितने हस्पताल खोले गए हैं। साथ ही साथ यह भी पूछा है कि नारायणगढ़ में श्री लाल सिंह जी के मन्त्री बनने के बाद कितने हस्पताल खोले गए हैं। मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि राज्य में इस समय कुल प ा चिकित्सालयों, डिस्पैन्सरियों तथा केन्द्रों की संख्या 1604 है। इन 1604 में से 77 तो भाहरों में है और बाकी 1527 देहातों में हैं।

चौधरी इन्दं सिंह नैन : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने इस सवाल के ''बी'' भाग में बताया है कि प ा चिकित्सक के 61 पद, प ा औशधक के 62 पद और प ाधन सहायक के 40 पद रिक्त हैं। साथ ही इन्होंने अपने सवाल के ''सी'' भाग में यह भी बताया है कि खाली पद इसलिये, नहीं भरे गए क्योंकि सरकार ने रिक्त पदों को भरने पर बैन लगाया हुआ है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इन रिक्त पदों का कारण योग्य (ट्रेन्ड) डाक्टर्ज व स्टाक एसिस्टैन्टस न मिलना तो नहीं है ? यदि योग्य डाक्टर्ज व स्टाक एसिस्टेन्ट्स नहीं मिल रहे तो क्या नए ट्रेनिंग सैन्टर खोल कर ऐसे डाक्टर्ज व स्टाक एसिस्टेन्टस तैयार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

चौधरी भजन लाल : जो बात नैन साहब ने कही है उस पर हम जरूर विचार करेंगे यदि ट्रेन्ड डाक्टर्ज आदि हमें नहीं मिलेंगे तो ट्रेनिंग देने आदि का भी प्रबन्ध किये जाने पर विचार

किया जा सकता है। मैंने पहले भी कहा है कि जहां रिक्त पद पड़े हैं और उन पदों को भरा जाना उचित समझा जायेगा तो बैन में ढील देकर उन पदों को भर दिया जायेगा। हमारी पूरी कोि ा ा होगी कि जहां इन पदों को भरा जाना उचित होगा, उनको 31 मार्च तक भरने की कोि ा ा करेंगे।

Mr. Speaker : Question hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र न का लिखित उत्तर

Abolition of Octroi Duty in the State

***1075. Shri Nihal Singh :** Will the Minister of State for Local Government be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to abolish octroi duty in the State;

(b) if so, the total amount of estimated loss to be suffered by the Municipal Committees due to abolition of octroi duty; and

(c) the proposal, if any, to meet the aforesaid loss ?

स्थानीय भाासन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रका ा महाजन) :

(क) हां।

(ख) अनुमानित हानि लगभग 15 करोड़ रुपये वार्शिक होगी।

(ग) प्रवे ा भाुल्क अथवा अन्य उपयुक्त कर लगाने से सम्बन्धित वैकल्पिक प्रस्ताव का निरीक्षण किया जा रहा है।

गैर–सरकारी प्रस्ताव

(i) भााह आयोग द्वारा हरियाणा के पक्ष में अवार्ड किए गए सभी क्षेत्रों की हरियाणा राज्य में ट्रांसफर करने सम्बन्धी (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब भााह आयोग अवार्ड को इम्पलीमैंट करने सम्बन्धी रैजोल्यू ान पर, जो डा0 मंगल सैन (अब एक्स एम0 एल0 ए0) ने 28–3–85 को मूव किया था, पर डिसक ान रिज्यूम होगी।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। डा0 मंगल सैन, जिन्होंने यह रैजोल्यू ान मूव किया था, अब हाउस के मैम्बर नहीं हैं। भाायद विज साहब इस पर कुछ बोलना चाहते लेकिन वो भी हाउस में नहीं आये हैं। इसके अलावा, इस रैजोल्यू ान पर काफी डिसक ान हो चुकी है और अब इसका उतना महत्व भी नहीं रहा क्योंकि मैथ्यू कमी ान ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हाउस की सैन्स ले लें और यदि हाउस कंसैंट देता है और आप ठीक समझते हैं तो इसे विदड्रा किया हुआ

समझा जाए और अगले रैजोल्यू ान पर, जो इससे भी ज्यादा महत्व का है, डिसक ान भाुरू कर ली जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that the resolution be deemed to have been withdrawn ?

Voice : Yes.

The Resolution was, by leave of the House, deemed to have been withdrawn.

(ii) पंजाब क्षेत्र में एस0आई0एल0 नहर के निर्माण में देरी सम्बन्धी।

श्री अध्यक्ष : अब श्री इन्द्र सिंह नैन, एम0 एल0 ए0 अपना रैजोल्यू ान मूव करेंगे।

Chaudhari Inder Singh Nain (Barwala) : Sir, I beg to move-

"This House recommends to the State Government to approach the Central Government to immediately take over the construction of the S.Y.L. Canal in the Punjab Territory in their own hands so that the same is completed without any further delay. The delay in the construction of the said canal has already greatly affected the economy of the State and increasing the cost of construction thereof tremendously."

Mr. Speaker : Motion moved-

"This House recommends to the State Government to approach the Central Government to immediately take over the construction of the S.Y.L. Canal in the Punjab Territory in their own hands so that the same is completed without any further delay. The delay in the construction of the said canal has already greatly affected the economy of the State and increasing the cost of construction thereof tremendously."

11.00 बजे

चौधरी इन्द्र सिंह नैन : स्पीकर सर, अभी अभी मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है क्योंकि इसका सम्बन्ध पानी से है। हरियाणा कृशि प्रधान प्रांत है और पानी इसके लिये बहुत महत्व की चीज है। इसलिए इस रैजोल्यू ान को प्रस्तुत करते हुए मुझे गौरव भी महसूस हो रहा है और खु ाी भी हो रही है। यह बहुत ही जनहित की बात है। स्पीकर सर, मैं आ ाा रखता हूं कि यह हाउस सर्वसम्मति से इस रैजोल्यू ान को पारित करेगा। अच्छा होता अगर अपोजी ान के भाई भी आज यहां उपस्थित होते और जनहित की बात यहां आकर कहते तथा पोजी ान और अपोजी ान दोनों मिल कर हरियाणा के हित में, हरियाणा के इंट्रैस्ट में, मिलकर सर्वसम्मति से इस रैजोल्यू ान को पास करते। लेकिन बड़े दु:ख से कहना पड़ता है कि अपोजी ान के भाई यहां नहीं आए। इससे साफ जाहिर होता है कि उनको हरियाणा के हितों में कोई इंट्रैस्ट नहीं है। वे तो वैसे ही मगरमच्छ के आसूं बहाते हैं। हरियाणा की जनता की बात यहां आकर कहने की बजाय लोगों को सड़क पर

घसीट लेते हैं। जहां उन्हें बात कहनी चाहिए, जहां प्रोपर फोरम है, वहां वे बात नहीं कहते। अध्यक्ष महोदय, यह जो रैजोल्यू ान मैंने अभी मूव किया, जैसा मैं पहले कह चुका हूं, बड़ा महत्वपूर्ण रैजोल्यू ान है। स्पीकर सर 1 नवम्बर, 1966 को हरियाणा का जन्म हुआ। स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने अपनी कलम से हरियाणा बनाया था। उससे पहले हरियाणा और पंजाब इकट्ठे थे। जिस तरह दो भाई अलग–अलग हो जाते हैं हरियाणा और पंजाब भी अलग हुए। पंजाब हमारा बड़ा भाई है। हरियाणा उसका छोटा भाई है। स्पीकर सर, आप तो काफी तजुर्बा रखते हैं और आपको सारी बातों का पता है। ज्वायंट पंजाब में हरियाणा के क्षेत्रों में बिल्कुल तरक्की नहीं होती थी। सारा पैसा, मैं तो कहता हूं 80 परसैन्ट पैसा, पंजाब के एरियाज में खर्च होता था और बहुत कम पैसा हरियाणा के एरियाज में लगता था। लेकिन बड़ी खु ाी की बात है कि अलग होने के बाद हरियाणा प्रान्त ने काफी तरक्की की और आज यह हिन्दुस्तान के नक ो पर सूर्य की तरह चमकता है। यह तरक्की क्यों हुई है ? मैं कह सकता हूं कि अलग होने से हुई है। अगर हम इकट्ठे रहते तो यह तरक्की नहीं हो सकती थी क्योंकि कमांड उनके हाथ में थी, मुख्य मन्त्री उनका बनता था। स्पीकर सर, यह तो मैंने बैकग्राउन्ड बताई। अब बात आती है सिंचाई की। सिंचाई के लिए पानी बहुत जरूरी है। मैंने कल भी कहा था कि एस0वाई0एल0 कैनाल हमारी लाईफ लाईन है। हरियाणा की सारी इकौनोमी इस पर डिपैन्ड करती है। कृशि प्रान्त होने के नाते महेन्द्रगढ़, गुड़गांव, भिवानी और दूसरी जगहों

के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तो किसान फैमिली से ताल्लुक रखता हूं, गांव का रहने वाला हूं और किसानों के दुःख को जानता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि सर्दी और गर्मी में रात तथा दिन को खेतों में पानी लगाते समय किसान को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसान को जब पानी मिल जाता है, उसकी फसल हरी भरी हो जाती है तो वह बहुत खु ा हो जाता है क्योंकि खेती के सिवाए उसकी कोई आमदनी नहीं होती। अगर समय पर वर्शा न हो, मौनसून न आए, तो किसान निरा ा हो जाता है। इसलिए इस नहर का बनना बहुत जरूरी है। आज सारे हरियाणा की जनता हमारी तरफ जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनकी और सरकार की तरफ देखती है। अपोजी ान के भाई लोगों को मिसलीड करते हैं, गलत बातें कहते हैं। वे तो यहां तक कहते हैं कि अब जो पानी मिल रहा है यह भी नहीं मिलेगा। वे तोड़ मरोड़ कर बातें करते हैं और लोगों के सैंटिमैंट्स को भड़काते हैं। ऐसी बातें करके ही वे 23 तारीख को लोगों को सड़क पर ले आए, सारे कीकर के दरख्त काट डाले लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि इस तरह से लोगों को मरवाने और सरकार को गाली देने से तरक्की नहीं होती। तरक्की होती है प्रोग्राम बनाने से और स्कीमें बनाने से। ये बातें वे कर नहीं सकते। स्पीकर सर, 1976 में जो ऐग्रीमैंट हुआ था उसके तहत हरियाणा प्रान्त को 3.5 एम0 ए0 एफ0 पानी दिया गया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और चौधरी बंसी लाल जी मुख्य मन्त्री थे। कांग्रेस की सरकार ने यह हिस्सा हमें दिलाया था लेकिन अफसोस

यह है कि पंजाब के एरिया में नहर नहीं खुद सकी जबकि हरियाणा के एरिया में यह बन गई। स्पीकर साहब, पंजाब में नहर नहीं बन रही है वहां पर अभी रूकावट पड़ी हुई है लेकिन हरियाणा में बन चुकी है। इसलिए मैं इस नहर के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बतलाऊंगा। हरियाणा के हिस्से में एस0वाई0एल0 कैनाल बनी है और यह सन् 1980 में बन कर तैयार हो गई थी। आज उसे बने हुए पांच छः साल हो चुके हैं। उस नहर की मैनटेनैन्स पर बड़ा भारी पैसा लग रहा है। यह नहर बिना पानी के खराब हो रही है, जगह–जगह से टूटी हुई है। उधर दूसरी तरफ यानी पंजाब के अन्दर एस0वाई0एल0 कैनाल ने बनने के कारण यह हालत हो रही है और हरियाणा को पानी नहीं आ रहा। यह बड़े दुःख की बात है कि पंजाब के भाई इस नहर को नहीं बनने देते हैं। पंजाब के भाईयों की तो यह पोजी ान है कि जो नहर पहले की बनी हुई है, उसे भी काट देते हैं। भाखड़ा का पानी भी हरियाणा में नहीं आने देना चाहते। दूसरी तरफ चौधरी देवी लाी जी बात करते हैं कि पंजाब का मुख्य मन्त्री सरदार प्रका ा सिंह बादल होना चाहिए। ये उनके बारे में बात करते हैं जो हमें पानी नहीं देते और हमें नुक्सान करते हैं। वे हरियाणा में पंजाब की बात करते हैं। स्पीकर सर, हरियाणा में जो नहर बनी है उस पर 31 करोड़ रुपया लगा था। यह 31 करोड़ रुपया सन् 1980 में 93 किलोमीटर नहर पर लगा था। लेकिन आपको पता है कि आज के दिन महंगाई बढ़ चुकी है इसलिये पंजाब साईड पर जो एस0वाई0एल0 बनेगी उस पर बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। अगर यह

नहर उस जमाने में बन जाती जब हमारी बनी थी तो हमारा बहुत पैसा बच सकता था। आज हमें पंजाब प्रान्त को बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है जिसके कारण हरियाणा का बड़ा भारी लौस हो रहा है। स्पीकर सर, पंजाब के एरिया के अन्दर जो नहर बननी है वह 120 किलोमीटर लम्बी बननी है। हमारे एरिये में जो 93 किलोमीटर नहर बनी उस पर 31 करोड़ रुपया लगा है जबकि 120 किलोमीटर पर 270 करोड़ रुपया लगेगा। यह मैं आंकड़ों से बता रहा हूं कि हमें पंजाब के एरिया में नहर बनाने के लिए कितना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। उस जमाने में तो 93 किलोमीटर नहर 31 करोड़ रुपये में तैयार हो गई थी लेकिन अब पंजाब के एरिया में 120 किलोमीटर नहर बनाने के लिए 270 करोड़ रुपया लगेगा। इससे हरियाणा की इकोनोमी भौटर करेगी। पंजाब के एरिया में जो नहर बनेगी उसके लिए हमने 110 करोड़ रुपया पंजाब गवर्नमैंट को दिया है और 90 करोड़ अभी देना बाकी रहता है। पैसे के लिये हरियाणा सरकार की तरफ से किसी किस्म की कोई कमी नहीं रही है। हमने हर जगह से पैसा काटकर, दूसरे प्रोग्रामों को कट करके इस कैनाल के लिए पैसा दिया है। हमारी सरकार ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। पंजाब वाले हमारे बड़े भाई हैं लेकिनवे इस कैनाल को नहीं बनने दे रहे। कल क्वै चन आवर के समय भी यह बात आयी थी उस समय यह भी कहा गया था कि जो पैसा हरियाणा सरकार की ओर से दिया गया है, वह कोठियों पर लग गया है या किसी और जगह पर लगा है लेकिन मैं केवल इतना कह सकता हूं ि कवह पैसा प्रौपर्ली खर्च नहीं हो

रहा है। अगर यह पैसा ठीक तरह से खर्च होता तो अब तक नहर बन जाती लेकिन ठीक तरह खर्च न होने के कारण नहीं बनी।

स्पीकर सर, जब यह एस0वाई0एल0 नहर बन कर तैयार हो जायेगी तो इस कैनाल से छः लाख हैक्टेयर रकबा इरीगेट होगा। हरियाणा मालामाल हो जायेगा और लोग बड़े खु ा होंगे, किसान सरकार को दुआएं देंगे। जब किसान का नाका कटेगा तो हरियाणा की सरकार को याद करेंगे कि हमारे लिए कितना बड़ा कार्य इस सरकार ने किया है। किसान के लिए पानी से ज्यादा बड़ी बात कोई नहीं होती। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि किसान के लिए खेती ही सब कुछ है। नहर से छः लाख हैक्टेयर जमीन की आबपा ाी होगी। आप अन्दाजा लगायें कि हरियाणा में कितना ज्यादा अनाज का उत्पादन बढ़ेगा।

स्पीकर सर, सन् 1977 में किन्हीं कारणों से कांग्रेस पार्टी हार गई और दूसरी पार्टी जीत गई। कांग्रेस पार्टी केवल हरियाणा प्रान्त में ही नहीं बल्कि सारे दे ा में हार गई। हमारे दे ा में एक नयी पार्टी की सरकार बनी, एक अनहोली गठन हुआ। सारी पार्टियों का गठन हुआ और उस गठन का नाम जनता पार्टी रखा गया। जब यह जतना पार्टी बनी थी, उस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने कहा था कि यह खिचड़ी पार्टी है। इनकी कोई आइडोलोजी नहीं है। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा भानमती ने कुनबा जोड़ा वाली कहावत बनेगी। वे सब इकट्ठे हुए थे लेकिन पूरे समय तक अपनी सरकार को नहीं चला सके। पांच

साल के लिए सरकार बनी थी लेकिन अढ़ाई साल में ही छोड़ कर चले गये। उस सरकार ने हमें जेलों में डाल दिया, इन्दिरा जी को जेल में डाल दिया लेकिन जनता पार्टी राज नहीं कर सकी। मैं तो उस समय कहा करता था कि जनता पार्टी की कोई नीति नहीं है, कोई पालिसी नहीं है इसलिये यह चल नहीं सकती और ऐसा ही हुआ। सन् 1977 में हरियाणा के मुख्य मन्त्री चौधरी देवी लाल जी बने और पंजाब में सरदार प्रका ा सिंह बादल बने। दोनों मुख्य मन्त्री अपने आपको दोस्त कहा करते थे लेकिन चौधरी देवी लाल जी इस नहर को नहीं बनवा सके। आज वे बात करते हैं कि हम किसानों को पानी दिलायेंगे, भाव दिलायेंगे। कहना आसान है लेकिन करना बड़ा मु कल है। किसी आदमी का तब पता लगता है जब उसे चान्स मिले और वह कुछ काम करके दिखाये। अगर वह अपने समय में काम करने में फेल हो जाता है तो जनता उसे दोबारा चान्स नहीं देती। जब जनता ने किसी आदमी को काम करने का मौका दिया हो और वह अपनी परफौरमैंस अच्छी न दिखा सके तो उससे जनता नाराज हो जाती है और फिर मौका नहीं देती। स्पीकर साहब उस समय सैन्टर में भी उनका राज था ओर अकाली भी जनता पार्टी के साथ मिले हुए थे। सुरजीत सिंह बरनाला जो आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, वे उस समय केन्द्रीय सरकार में मिनिस्टर थे लेकिन इन लोगों ने एस0वाई0सल0 नहर नहीं बनवायी। अगर ये किसान का भला चाहते थे, किसान के रखवाले थे तो उनको उस समय मौका मिला था, उस समय उनकी सहायता कर सकते थे। इनका अपना राज

था, पंजाब के एरिया में नहर तैयार करवाते ताकि इन्हे हरियाणा की जनता तथा इतिहास याद रखता। अगर वे आज यहां होते तो हम इन्हें यह कहते कि उन्होंने हरियाणा की जनता के लिए कुछ किया है। वे बाहर जनता में तो बोलते हैं लेकिन यहां सामने नहीं आते। उन लोगों को हाउस में आना चाहिए था कन्स्ट्रक्टिव सुजै ान देनी चाहिए थी और हम उनकी बात का यहां जवाब देते तो सारे हरियाणा का भला होता। अपोजी ान अपनी डियूटी में कोताही कर रही है और पब्लिक ने जो उन्हें डियूटी दी है उसमें कोताही कर रही है। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें जनता कभी नहीं बख्भाती। यहां हाउस में आ कर तसे वे अपनी बात नहीं कहते हैं लेकिन गांवों में जा कर लोगों को बहकाते हैं। मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और लोगों के सामने कहते हैं कि हरियाणा सरकार परनी नहीं दिलायेगी। हरियाणा के साथ बे–इन्साफ हुआ है, हरियाणा के मुख्य मन्त्री जनता का गला घोंट रहे हैं लेकिन उन्हें अपने ग्रेबान में मुहं डाल कर देखना चाहिए कि वे क्या कुछ कर रहे हैं। कथनी और करनी में फर्क नहीं रखना चाहिए। असलियत तो यह है कि जब उन लोगों को मौका मिला था और उनका राज था, उस वक्त नहर को बनाते लेकिन उस समय यह नहर को नहीं बना सके। उस समय अकालियों की कोई मांग नहीं थी लेकिन जब अकाली राज चला गया तो इनकी मांग आ गयी। स्पीकर साहब जो आज के दिन पंजाब के हालात हैं वे आपके सामने हैं। अगर इस बारे में हम बहस करने लगें तो कई दिन लग

जायेंगे। आज दे ा की बदकिस्मती है कि धर्म और एरिया के नाम पर हिन्दुस्तान को अलग–अलग करना चाहते हैं।

स्पीकर सर, मुझे दो साल पहले एडवान्स कन्ट्रीज में जाने का मौका मिला था। आज के दिनों में एडवान्स कन्ट्रीज रूस और अमेरिका हैं। वहां के लोग बड़े दे ाभक्त हैं। वे अपनी ड्यिूटी के बड़े पक्के हैं। वे लोग अपने कर्तव्य को समझते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान के लाग इस बात को नहीं समझते। मैं तो यह कहूंगा कि इस मामले में केन्द्रीय सरका को तगड़े कदम उठाने चाहिए। यह बात लचीली पालिसी से बनने वाल नहीं है। जो व्यक्ति कमजोर है उसको ऊंचा उठाने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिएं। भाराफत का मतलब यह नहीं होता कि वह इन्सान कमजोर है।

स्पीकर साहब, मैं एक बात कह सकता हूं, भाायद मुख्य मंत्री जी मेरी इस बात की ताईद करेंगे कि अकालियों की नीयत या उनकी मन् ाा इस नहर को बनाने की नहीं है। आप अखबारों में भी पढ़ते हैं। आपको तो सारी बातों का इल्म है। प्रका ा सिंह बादल भूतपूर्व मुख्य मंत्री, जब किसानों की एजीटे ान हुई, तब उनके साथ थे। जैसे सिंचाई मंत्री जी ने बताया कि किसान अभी भी एलाइनमैंट की बात पर एजीटे ान कर रहे हैं, हालांकि एक्सपर्ट कमेटी ने फैसला दे दिया है कि यह सबसे बढ़िया एलाइनमैंट है वास्तव में देखा जाये तो वहां पर किसान एजीटे ान नहीं कर रहे हैं, उनको पीछे से प्रका ा सिंह बादल

का इ ाारा है। वह यह चाहते हैं कि यह नहर न बने। उनकी आपस की लड़ाई में मैं नहीं जाना चाहता। उनका अपना मामला कुछ भी हो सकता है वह चाहते हैं कि यह नहर ने बने। सुरजीत सिंह बरनाला की कुर्सी गिर जाये। किसान सरकार की स्पोर्ट के बिना इतनी देर तक एजीटेड नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा, वह यह नहीं चाहते कि नहर बने क्योंकि उनकी राजनीति इस किस्म की है। यह बड़ी ही खु ाी की बात है कि हरियाणा गवर्नमैंट ने अपना स्टैंड पे ा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमारे सिंचाई मंत्री जी वहां पर कई बार गये और हमारे मुख्य मंत्री जी अपना नाम हिट–लिस्ट में होते हुए भी नहर को देख कर आये हैं। अभी प्रधान मंत्री जी मौके पर जाकर नहर की इन्सपैक ान करेंगे ताकि असलीयत का पता चले। स्पीकर साहब, नहर बननी बहुत ही जरूरी है। वह यह चाहते हैं कि नहर न बने और इसी तरीके से काम चलता रहे। हमें बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि यह पानी पाकिस्तान में तो जा सकता है लेकिन हमें नहीं मिल सकता। पंजाब हमारा बड़ा भाई है और हम उसके छोटे भाई हैं। भाई कई बार अलग–अलग हो जाते हैं। कोई नई बात नहीं है। लेकिन यह बड़े दुःख की बात है कि हिन्दुस्तान का पानी पाकिस्तान को तो जा सकता है लेकिन हरियाणा, जो एक छोटा भाई है, उसको नहीं दिया जा सकता। कुछ नहरों की नैचुरल ढलान पंजाब साईड पर है। फिरोजपुर से आगे जितनी भी नहरें हैं, वे पंजाब में जाती हैं। जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो हिन्दुस्तान ने इस पानी के पैरो पाकिस्तान

गवर्नमैंट को दिये थे यानी मुआवजा दिया था। यह पानी तो हमारा खरीदा हुआ है। यह पानी हमारा है जोकि पाकिस्तान में जा रहा है। इससे ज्यादा दुःख की बात और क्या हो सकती है कि वह हमें तो पानी द दें और वह पानी पाकिस्तान में जाने दें। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि दे ा प्रेम की भावना उनके मन में होनी चाहिये। पंजाब के अन्दर वाटर लागिंग हो रही है, सीपेज हो रही है, पानी की उनको उतनी जरूरत नहीं है, इस सब के बावजूद भी, जैसे मैंने पहले कहा, हरियाणा जिसको पानी की जरूरत है, उसको पानी नहीं दे रहे हैं। हरियाणा को पानी की आज बहुत ज्यादा नसैसिटी है और उनको कोई खास जरूरत नहीं है। वह तो पानी फालतू ले रहे हैं। हमे पानी की जरूरत है, हमें वे पानी देते नहीं हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हरियाणा पहले ही काफी तरक्की कर रहा है। अगर यह नहर बन जाये तो हिन्दुस्तान में पहले स्थान पर आ सकता है, हालांकि कई मामलों में तो हरियाणा अब भी पहले स्थान पर रहा है। जब तक सैंटर मजबूत कदम नहीं उठाता, पंजाब सरकार वहां पर नहर बनने नहीं देगी। जब तब सैंटर इस नहर का काम अपने हाथ में नहीं लेगा तब तक अकालियों की पंजाब सरकार यह नहर बनने नहीं देगी। वहां पर कोई भी यह नहीं चाहता कि यह नहर बने। एक बात उनके दिमाग में है कि वह तो बड़े मजबूत हैं और जो चाहेंगे वहीं करेंगे या करायेंगे। मैं एक बात अव य कहना चाहूंगा कि हरियाणा के लाग इतने कमजोर नहीं हैं, जब तब वे बर्दा त कर हरे हैं तब तक तो कर रहे हैं लेकिन जब किसी चीज की हद हो

जाती है तो हमारे पंजाब वाले भाई इस बात को याद रखें कि हम किसी से भी कम नहीं हैं। हम अपना हक लेना जानते हैं हम इसलिये सैंटर से अनुरोध कर रहे हैं ि कवह इस काम को पने हाथ में ले और मजबूती के साथ इस नहर को बनायें। जब तक सैंटर इस नहर को अपने हाथ में नहीं लेगा, यह नहर नहीं बनेगी। स्पीकर साहब, अपोजी ान के भाई आज यहां पर नहीं हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा रूलिंग पार्टी के साथ–साथ अपोजी ान का होना भी लाजमी है। डैमोक्रेसी तभी कम्पलीट होती है जब उसमें अपोजी ान हो। Opposition is an essential part of democracy. डैमोक्रेसी में दोनों ही जरूरी है। गाड़ी के दो पहिये हैं, दोनों का होना बहुत जरूरी है। वह हाउस में आयें, अपनी बात कहें। आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है लोक दल वाले भी नहीं है। आज कोई भी अपोजी ान पार्टी यहां पर नहीं है। स्पीकर साहब, कई बार यह लोग गठजोड़ कर चुके हैं। डाक्टर मंगल सैन, जनता पार्टी के साथ और लोक दल के साथ कई बार गठजोड़ कर चुके हैं। यह इनकी अनहोली एलाऐन्स कई बार हो चुकी है लेकिन यह ज्यादा देर नहीं चलती। पता नहीं कैसा जहर दिया हुआ है किसारे ही पीछे लगे हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि क्या होगा। उनकी आपस में आइडीओलोजी नहीं मिलती, उनके विचार नहीं मिलते। एक भाहर की बात करते हैं, दूसरे गांव की बात करते हैं। दोनों का रास्ता एक कैसे हो सकता है ? पता नहीं, यह अनहोली एलाएन्स पहले कितनी बार टूटी है। यह ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। पता नहीं कैसे लोक दल वाले

भारतीय जनता पार्टी वालों के पीछे लगे हुए हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा जिससे यह बात साफ हो जायेगी कि उनकी क्या पोजी ान है। भारतीय जनता पार्टी के भाई लोक दल के साथ लगे हुए हैं, यह मिसाल इन पर फिट बैठती है। मैं देहात का रहने वाला हूं। आप भी स्पीकर साहब, देहात से ताल्लुक रखते हैं। एक गांव में कोई कुम्हार रहता था। वह पदावा लगाता था जिसको पंजाबी लोग भट्टा कहते हैं। उसने गधे रखे हुए थे। वह उनसे कूड़ा वगैरा उठाकर पदावे में डालता था। जब रात हो जाती थी तो जो उसका वाड़ा था, उसमें वह उन गधों को एक रस्सी से बांध देता था। वह एक मुट्ठी में रस्सी लेकर एक–एक करके एक के बाद दूसरे गधे को एक ही रस्सी से बांध देता था। यह उसका प्रत्येक रोज का काम था। एक दिन क्या हुआ। वह रस्सी कहीं गुम हो गयी। उसको बड़ी चिन्ता हो गयी। चिन्ताग्रस्त वह बैठा हुआ था कि अव कैसे इन गधों को बांधूंगा। अगर नहीं बांधूंगा तो चले जायेंगे। फिर क्या बनेगा? इतने में उसके पास कुम्हारी आ गयी। वह कहने लगी कि उदास क्यों हो। चिन्ता किस बात की है। वह कहने लगा कि चिन्ता यह है कि रस्सी आज गुम हो गयी, इन गधों को बांधंगा कैसे। नहीं बांधूंगा तो ये कहीं न कहीं चले जायेंगे। वह कुम्हारी बड़ी समझदार थी, इन्टैलीजैंट थी। वह कहने लगी, कोई बात नहीं है। यह तो कोई सीरियस प्रौब्लम ही नहीं है। कहने लगी सारे गधों को उसी तरह इकट्ठा खड़ा कर दो। जैसे पहले मुट्ठी भर कर बांधा करते थे, उसी तरह स`अब बिना रस्सी के बांध दो। स्पीकर सर, उस कुम्हार ने वैसा ही किया। एक

मुट्ठी भर ली। कुम्हारी ने जिस तरह से समझाया था, वह बांधता गया। सारे गधे रात भर वहीं पर खड़े रहे। कोई भी वहां से नहीं हिला। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से मुट्ठी भर कर रस्सी से बांध रखा है, इससे फालतू कोई बात नहीं है। आप भी महसूस करेंगे कि यह गलत बात है जो वे कर रहे हैं। प्रजातन्त्र में सबसे बड़ी बात जनहित की रक्षा करना होती है। उनको पब्लिक इन्ट्रैस्ट वाच करना चाहिये। मैं तो एक बात जानता हूं कि जो इन्सान इलैक्ट होकर आता है, उसको अपना फर्ज भी पूरा करना चाहिये। उसका फर्ज है कि वह यहां पर आये और असली मायनों में लोगों की नुमायन्दगी करे। लोगों की बात कहने के लिये यह सही प्लेटफार्म है। असल और नकल की वह पहचान करे। मैं अधिक समय न लेता हुआ अन्त में एक बात और कहना चाहूंगा। इस नहर का काम सैंट्रल गवर्नमैंट को अपने हाथ में लेना चाहिये। यह जो रैज्योलू ान मूव किया गया है, यह हमस ब को सर्वसम्मति से पास करना चाहिये। अपोजी ान के भाई, जो यहां पर नहीं आये हैं, जनता कभी भी उनको मुआफ नहीं करेगी। जनता एक–एक चीज को देखेगी। वह जब पूछेगी कि तुमने क्या किया तो ये क्या जवाब देंगे ? आज समय था कि सब इकट्ठे होकर, मिलकर अपोजी ान और पोजी ान के भाई हरियाणा के हितों के लिये इकट्ठे बात करते। वे यहां आकर अपनी बात कहते और सर्वसम्मति से यह रैज्योलू ान पास करते। लेकिन वे तो यहां पर आये ही नहीं। उनकी राजनीति कंस्ट्रक्टिव नहीं है। स्पीकर सर, आपको मैं क्या बताऊं। आप सब पार्टीज को अच्छी तरह से जानते हो। मैं तो

पहली बार चुन कर आया हूं। आप तो तजुर्बे वाले आदमी हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इस नहर को बनवाना बहुत जरूरी है। यह डैथ और लाइफ का सवाल है, हमारी जिन्दगी और मौत का सवाल है। स्पीकर साहब, आप किसान के मन की बात समझ सकते हैं। किसान के लिए नहर बननी बहुत जरूरी है। स्पीकर साहब, अगर यह नहर नहीं बनती तो लोग हमें माफ नहीं करेंगे यह बात याद रखने की है। गांव में जाकर देखें कि लोगों की क्या भावना है और उनको समझना बहुत जरूरी है। किसान के लिए पानी बहुत जरूरी चीज है। स्पीकर साहब, मैं अन्त में यही प्रार्थना करूंगा कि सर्वसम्मति से यह रैजोल्यू ान पास किया जाए और सैन्टर्ल गवर्नमैंट पर मुख्य मन्त्री, सिंचाई मंत्री और हम जितने भी साथी हैं सब मिलकर इस बारे में जोर दें, तगड़ी वकालत करें ताकि नहर का काम जल्दी सैन्टर्ल गवर्नमैंट अपने हाथ में ले। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करात हूं।

ि ाक्षा राज्य मन्त्री (श्री जगदी ा नेहरा) : अध्यक्ष महोदय, जो हाउस के सामने नौन औफि ियल रैजोल्यू ान है, मैं उसकी ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिस तरह से माननीय सदस्य ने पहले कहा है कि एस0वाई0एल0 का सवाल हरियाणा के लिए जिन्दगी और मौत का सवाल है, मैं भी इस वास्तविकता को मानता हूं कि यह हरियाणा के लिए मौत और जिन्दगी का सवाल है। जब तक किसान के पास पानी नहीं है

किसान की जिन्दगी नहीं है। स्पीकर साहब, 3.5 एम0ए0एफ0 पानी हरियाणा के लिए मौत और जिन्दगी है और किसान के लिए खु ाहाली ला सकेगा। स्पीकर साहब, अगर इसके पीछे के इतिहास को लें तो करीब दस–ग्यारह साल पहले यह समझौता हुआ था। हरियाणा सरकार ने आगे इस पानी को ले जाने के लिए एस0वाई0एल0 कैनाल बनाई और दस समय करीब सौ करोड़ रुपया खर्च किया और यह इसलिए किया कि पंजाब से पानी आने के बाद यह हरियाणा के खेतों की सिंचाई करेगा। इसीलिए यह सौ करोड़ रुपया लगया गया। 1976 में यह फैसला हुआ। उसके बाद 1977 में कांग्रेस पार्टी हार गई और जनता पार्टी का राज्य आया तो जनता पार्टी में उस समय वे लोग थे जो आज विपक्ष में हैं। विपक्ष के ये भाई उस समय सरकार में होते थे। उस समय इन भाईयों ने कोई भी काम एस0वाई0एल0 के लिए नहीं किया। उस समय पंजाब के मुख्य मन्त्री सरदार प्रका ा सिंह बादल और हरियाणा के मुख्य मन्त्री चौधरी देवी लाल थे। ये दोनों एस0वाई0एल0 के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) डिप्टी स्पीकर साहब, उस समय सारा मामला सुलझ सकता था। हालात उस समय पंजाब में भी और हरियाणा में भी ठीक थे। दोनों दोस्त थे। हरियाणा को पानी की जरूरत थी। दोनों की साजि ा से या इस चीज को महत्व न देने की बात समझकर एस0वाई0एल0 के मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गए और दो तीन साल तक यह मामला कोर्ट में लटका रहा। डिप्टी स्पीकर साहब, 1980 में जब कांग्रेस पार्टी दुबारा सत्ता में

आई तो श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दोनों मुख्य मन्त्रियों को बुलाकर समझाया और 1981 में एक समझौता हुआ। इसके बाद कर्पूरी गांव में श्रीमती इन्दिरा गांधी इस नहर का उद्घाटन करने खुद आई। उस समय पंजाब के मुख्य मन्त्री सरदार दरबारा सिंह और हरियाणा के मुख्य मन्त्री चौधरी भजन लाल मौजूद थे। वहां पर काम भाुरू हुआ। उस समय केन्द्रीय सरकार और हरियाणा सरकार ने काफी दिलचस्पी नहर खुदवाने में दिखाई और चाहा कि यह नहर जल्दी से जल्दी खुदकर तैयार हो लेकिन उसी समय अकालियों ने, जिनकी सरकार आज पंजाब में है, ऐजीटे ान भाुरू कर दिया। यह हालात खराब करने की बात है, नहर न खोदने की बात है। 1981 में जिस दिन श्रीमती इन्दिरा गांधी कर्पूरा गांव में आई थी उसी दिन अकालियों ने यह मुहिम भाुरू की थी और अराजकता के हालात पैदा किये। उसके बाद पंजाब में राश्ट्रपति भाासन हुआ। हालात अकाली पार्टी ने इतने खराब कर दिए कि दे ा की अखंडता को खतरा पैदा हो गया। यह सब अकाली पार्टी की देन है कि एस0वाई0एल0 नहर न खुद सकी। हरियाणा की कांग्रेस पार्टी हमे ाा इस बात की कोि ा ा करती रही कि हालात सुधरें और एस0वाई0एल0 नहर जिससे हरियाणा को 3.5 एम0ए0एफ0 पानी मिलना है, वह जल्दी बन सके और हरियाणा को पानी आ सके। लेकिन जब हालात न सुधरे तो 24 जुलाई, 1985 को राजीव लौंगोवाल समझौता हुआ। उस समझौते के तहत एस0वाई0एल0 नहर 15 अगस्त, 1986 तक तैयार हो जानी चाहिए थी, यह बात समझौते में तय हुई थी और इसको लागू करने के

लिए कोि ा ा की गई। यह कोि ा ा हरियाणा सरकार ने की कि किसी तरह यह नहर समय पर पूरी हो जाए। लेकिन हमारे जितने भी विपक्ष के भाई हैं उन्होंने इस समझौते को हिमायत नहीं की और आज भी ये विपक्ष के भाई कहते हैं कि वह समझौता गलत था। वे तो यहां तक कहते हैं कि टेरेटरी और पानी का जो समझौता हुआ वह बिल्कुल गल्त था। डिप्टी स्पीकर साहब, हिन्दुस्तान में किसी लीडर ने और दुनिया के किसी नीडर ने इस समझौते को गल्त नहीं बताया। केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी के लीडर, जनता पार्टी के लीडर, कांग्रेस (जे) के लीडर, मतलब यह कि किसी भी केन्द्रीय पार्टी के लीडर ने इस समझौते को गल्त नहीं बताया। उन्होंने यह कहा कि यह समझौता ठीक है और यह हरियाणा के लिए ठीक है। भारत की अखंडता के लिए यह समझौता ठीक है। लेकिन हरियाणा के विपक्ष के लोग कहते हैं कि यह समझौता ठीक नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, उनका यह कहना है कि पानी के समझौते में जो आंकड़े हैं, वे ठीक नहीं हैं। उनका मेन मुद्दा यह है कि 1981 में जो समझौता हुआ उसके मुकाबले 1985 में जो समझौता हुआ है उसमें हरियाणा को कम पानी दिया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, 1 जुलाई, 1985 को हरियाणा 1.9 एम0ए0एफ0 पानी ले रहा था और पंजाब 3.9 एम0ए0एफ0 पानी ले रहा था। मेरा कहना यह है कि इससे कम पानी हरियाणा और पंजाब को नहीं दिया जाएगा। विपक्ष का यह कहना कि 1 जुलाई, 1985 को हरियाणा 1.3 एम0ए0एफ0 पानी ले रहा था और पंजाब 6.2 एम0ए0एफ0 पानी ले रहा था, यह निराधार है। वास्तविकता

यह है कि हरियाणा उस दिन 1.9 एम0ए0एफ0 पानी ले रहा था और पंजाब 3.9 एम0ए0एफ0 पानी ले रहा था। डिप्टी स्पीकर साहब, 1976 में जो समझौता हुआ था उसके मुताबिक हरियाणा को 3.5 एम0ए0एफ0 पानी मिलना था और पंजाब को 4.2 एम0ए0एफ0 मिलना था। अब जो समझौता हुआ है उसके मुताबि 1 जुलाई, 1985 को हरियाणा 1.9 एम0ए0एफ0 पानी ले रहा था उससे कम पानी नहीं मिलेगा अधिक मिल सकता है। इसी तरह से पंजाब को 3.9 एम0ए0एफ0 से कम पानी नहीं मिलेगा अधिक मिल सकता है। डिप्टी स्पीकर साहब, यह समझौता न ता हरियाणा के विरूद्ध है और न ही पंजाब के विरूद्ध है। डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें सारा सिस्टम देखना पड़ेगा। इसमें राजस्थान भी भाामिल है। यह भी देखना पड़ेगा कि राजस्थान उस दिन कितना पानी इस्तेमाल कर रहा था। यह कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि बहुत से लोगों ने ऐकार्ड नहीं पढ़ा। देखना यह है कि उस दिन इरिगे ान के लिए, खेती के लिए वास्तव में कितना पानी लिया गया। यह नहीं कि नहर में कितना पानी चला। जो राजस्थान कैनाल जा रही है, उसमें भी उस दिन पानी चला है। कुल पानी 17.7 एम0ए0एफ0 है। पंजाब और हरियाणा ने जितना पानी लिया उससे बाकी पानी राजस्थान नहर में गया लेकिन नहर में जाने से कोई मतलब नहीं है। देखना यह है कि राजस्थान ने उस दिन इरिगे ान के लिए कितना पानी लिया। भाायद उस दिन उन्होंने इरिगे ान के लिए 3.5 एम0ए0एफ0 पानी लिया। इस तरह से कुछ एम0ए0एफ0 पानी राजस्थान से भी सरप्लस होगा। डिप्टी स्पीकर

साहब, बात इतनी ही है कि 1 जुलाई, 1985 को स्टेट इरिगे ान के लिए कितना वास्तविक पानी ले रही थी। इसका नहर में पानी जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। 1 जुलाई, 1985 को पंजाब 3.9 एम0ए0एफ0 पानी का इस्तेमाल कर रहा था। वास्तव में पंजाब भाायद इरिगे ान इतनी नहीं कर रहा है। इसलिये 'इरीगे ान' भाब्द की बजाये 'इस्तेमाल' का भाब्द समझौते में है और इससे हरियाणा को किसी भी ढंग से नुकसान होने वाला नहीं है लेकिन आज विरोधी दल के भाई यह कह रहे हैं कि पंजाब हरियाणा को पानी नहीं देगा। हरियाणा को पानी का नुकसान हो रहा है। उनकी यह बात बिल्कुल निराधार, बेबुनियाद है। ऐसी बातें करके उनका मकसद केवल लोगों को गुमराह करना और उकसाना है ताकि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े। ये लो उसी तरह का वातावरण हरियाणा में भी क्रिऐट करना चाहते हैं जैसा कि पंजाब में आजकल चल रहा है। ये लोगों को गुमराह करके गल्त रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, इस नहर का खुदाई का काम सन् अप्रैल 1981 में आरम्भ हुआ था, उस समय भी अकालियों ने इसके विरोध में धरना दिया था और उसके बाद अकाली विरोध स्वरूप असैम्बली में नहीं आए और वही नीति हमरो विरोधी पक्ष के भाईयों ने अपनायी है और वे इस सदन में नहीं आ रहे हैं। उल्टा लोगों को भड़का रहे हैं, उक्सा रहे हैं ताकि वे हरियाणा में सत्ता हथिया सकें। केवल सत्ता में आना ही उनका एक मात्र मुद्दा है। यदि विरोधी दल के भाई यहां पर आ जाते और विरोध स्वरूप बोल भी जाते तो उनको क्या दिक्कत थी ?

लेकिन यहां पर न आकर बाहर लोगों को गुमराह करकें, उकसा करके उनकी हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं। वे इतिहास को दोहराने की कोि ा ा कर रहे हैं। जिस तरह अकानी असैम्बली में नहीं गए थे उसी तरह वे भी सदन का बहिश्कार करेंगे। इससे लोगों को हमदर्दी होगी। यह सोचकर सब कुछ कर रहे हैं कि एक साल के अन्दर इलैक ान होने वाले हैं, उसमें हमारा फायदा होगा। वास्तविकता ता यह है कि विरोधी भाईयों ने कभी इस मामले में न तो स्वयं ही कोि ा ा की है, न ही कोई पैटी ान दी है और न ही पंजाब के भाईयों को उन्होंने समझाने की कोि ा ा की है। न ही केन्द्र को अपना रैजोल्यू ान दिया और न ही अपने केन्द्र के विरोधी भाईयों को कान्फीडैंस में ही लिया। फिर किस मुंह से विरोधी पक्ष वाले कहते हैं कि यह समझौता ठीक नहीं है, गल्त है। एक निराधार, बेबुनियाद अल्जाम है और वास्तविकता से दूर है। डिप्टी स्पीकर साहब, कांग्रेस सरकार की जो इन्टैन् ान है, उसको सभी जानते हैं कि यह सरकार दिल से चाहती है कि हरियाणा में पानी आए। इस का सबूत यह है कि हरियाणा ने 110 करोड़ 80 लाख रुपया पंजाब सरकार को दिया है और 2 करोड़ 50 लाख रुपये की म ाीनरी भी दी है। इसका मतलब यह हुआ कि 113 करोड़ 30 लाख रुपया हरियाणा सरकार ने अपने कम साधनों के बावजूद पंजाब सरकार को इसी काम के लिये दिया है। अब भी पंजाब सरकार के पास सरकार जमीन एक्वायर कर रही है और न ही अकाली सरकार यह चाहती है कि जमीन एक्वायर हो और काम चले। एक तरफ बरनाला जी कहते हैं

कि हम इसके लिये पूरी कोि ा ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ बादल साहब भारत किसान युनियम को लगातार इस काम में रूकावट डालने के लिये भड़का रहे हैं। पंजाब सरकार ने क्या किया है कि जो लोगों के मुआवर्ज की रमक 20 से 30 हजार रुपये तक की थी, उसको बढ़ाकर 70 से 80 हजार तक कर दिया है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं क्योंकि वही देने वाले हैं और उन्हीं की अपनी सरकार है। उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिये हैं कि न तो एक्वीजी ान करना चाहते हैं, न ही कोई काम करना चाहते हैं और न ही अफसरों को काम पर लगाना चाहते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब 30 करोड़ रुपया उनके पास पड़ा है, तो उनका यह फर्ज बनता है कि वे उस नहर में काम भाुरू करवाएं। कम से कम इस पैसे से एक्वीजी ान का काम तो पूरा करना चाहिये लेकिन वे इस काम को करने में बिल्कुल असमर्थता दिखा रहे हैं। उनकी नीयत साफ नहीं है। सन् 1981 से जब अकाली भाई विरोधी पक्ष में हुआ करते थे, उस दिन से इस काम के खिलाफ धरना देते रहे हैं, रास्ता रोकते रहे हैं और काम करने वालों को काम नहीं करने दिया। हम अब उनसे यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि नहर खुदे। जिन्होंने पिछले चार सालों में संघर्श किया हो कि यह नहर नहीं खुदनी चाहिये और अब तो वे सत्ता में हैं, इसी काम के लिये वे जेलों में गये, वही लोग क्या इस नहर को खुदने देंगे ? बिल्कुल खुदने नहीं देंगे। हमारे मुख्य मन्त्री महोदय और हमारी सरकार की सच्चे दिल से यह कोि ा ा रही है और वे समय–समय पर मीटिंगें भी करते रहे हैं और

चौधरी सुरजेवाला साहब भी मौके पर जाकर इस काम के लिये कोि ा ा करते रहे हैं। एक बार तो मैं भी उनके साथ गया था लेकिन लगातार इतनी कोि ा ाों के बावजूद भी यह नहर खुद नहीं रही है जबकि 113 करोड़ 30 लाख रुपया पंजाब सरकार को दे भी दिया है। 90 करोड़ रुपये का प्रोवीजन सरकार ने अपने इस साल के बजट में कम साधनों के बावजूद इस काम के लिये रखा है। इस तरह से 203 करोड़ 30 लाख रुपया सरकार ने इस काम के लिये दे रखा है। भोश पैसा पंजाब सरकार और केन्द्र सरकार ने देना है। थर्मल प्लांट के लिये जो पानी जाता है उसके लिये भी पंजाब सरकार ने पैसा देना है। मतलब यह कि हरियाणा सरकार की तरफ उनका एक पैसा भी बकाया नहीं है। 66 करोड़ के लगभग पंजाब और केन्द्र सरकार ने इस नहर के लिये देना है और आज विरोधी पक्ष के भाई यह कहते हैं कि हरियाणा सरकार ने पानी के लिये कुछ नहीं किया। लोगों को गुमराह करने, वरगलाने के सिवाये इन विरोधी भाईयों को और कोई काम नहीं है। कभी लोगों को कहते हैं कि रास्ता रोको। बन्द का आह्वान करो, कभी कहते हैं कि आन्दोलन करो। इन सभी बातों के पीछे उनकी इलैक ान जीतने की नीयत है क्योंकि अगले साल इलैक ान आ रहे हैं। लोगों से हमदर्दी जताओ, भाायद वे इन्हें पावर में ले आएं।

डिप्टी स्पीकर साहब, अपोजी ान के भाई आजकल एक और काम में लगे हुए हैं। वे 23 जनवरी को हुए दंगों में मरने

वाले लोगों के नाम से चन्दा इकट्ठा कर रहे हैं। लोक दल के नाम से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नाम से नहीं, चौधरी चरण सिंह के नाम से नहीं, मरने वालों के कफन के नाम से, उनके खुन के नाम से लोगों से पैसा बटोर रहे हैं। जो मरने वाले हैं, वे इनको पार्टी के आदमी नहीं थे न ही किसी और पार्टी से ताल्लुक रखते थे। उन बेसहारा लोगों को, अनजान लोगों को इस रास्ता रोको आन्दोलन से कोई सरोकार नहीं था। इसलिये जो चन्दा इकट्ठा किया जा रहा है या किया गया है, वह पैसा उन मरने वालों के घर वालों को दिया जाना चाहिये लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह काम ये लोग अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिये कर रहे हैं। कभी एस0वाई0एल0 का नाम लेते है, कभी एरियाज का नाम ले–लेकर लोगों को गुमराह करके भड़का रहे हैं। उनको इस बात का पता है कि इस काम में हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने दिल से कोि ा ा की है कि हरियाणा का ज्यादा से ज्यादा भला हो। अबोहर फाजिलका जा करके उस इलाके के लोगों को हम ने समझाया बुझाया। 15–20 दिनों तक हमने वहां बैठकर यह कोि ा ा की कि उनकी तरफ से एक रैजोल्यू ान लाया जाए। करीब 134 गांवों के लोगों से हमने रैजोल्यू ान लिया और उसके बाद कन्टूखेड़ा मिन्नी सैन्सस की बात हुई। हम सब ने मिलकर हरियाणा के हितों की रक्षा की। हम मिनिस्टर लोगों को जिस जगह पर जाने से जान का खतरा था, वहां पर भी गये क्योंकि जब पार्टी का, हमारे मुख्य मन्त्री महोदय का सब का यह फैसला था कि मिन्नी सैन्सस हो। इसीलिये हम सब वहां गये और लोगों

को समझाया बुझाया गया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपोजी ान के भाईयों ने न तो कोई इस प्रकार का रेजोल्यू ा ही पास किया और न ही कन्दूखेड़ा में जाकर हमारी इस स्थिति से निपटने के लिये मदद की और न ही उनका कोई आदमी वहां पर मौजूद था। उसके बाद मुख्य मन्त्री महोदय ने अपोजी ान के सभी पार्टियों के भाईयों की कई मीटिंगें बुलायी लेकिन उनमें कोई न आया। मुख्य मन्त्री महोदय दिल्ली में बैठकर भी इसी कोि ा ा में लगे रहे कि कहीं विरोधी पक्ष के भाई वहां पर आएं और उनसे इस बारे में सहयोग मिले लेकिन वहां भी कोई नहीं आया। मुख्य मन्त्री महोदय ने प्रधान मन्त्री जी के सहयोग से इस सारे वातावरण को संभाला। इसके बाद अपोजी ान के भाईयों ने, बजाये इसके ि कवे सरकार का साथ देते, रास्ता रोको आन्दोलन भाुरू करवाया, लोगों को उकसाया, भड़काया। यह सारा काम यह कहकर किया गया कि हमें एस0वाई0एल0 का पानी नहीं मिलेगा। बाऊंडरी एरिया में हरियाणा को नुकसान होगा। मुख्य मन्त्री जी ने यह फैसला किया कि यह जो रास्ता रोकने की बात है, यह हरियाणा के हितो की बात है, हम इसके बीच में नहीं आएंगे। बसें रोक दी गई, स्कूल कालेज बन्द कर दिए गए इसलिये बन्ध कामयाब था। सरकार भी चाहती थी कि आपस में लड़ाई हो। बाउंडरी एरिया के झगड़े पर और पानी के झगड़े पर पंजाब की सभी पार्टियां एक बात करती हैं लेकिन यहां पर विरोधी पक्ष के लोग अलग–अलग बातें कर रहे हैं। वे सरकार का साथ देने की बजाए लोगों से चन्दा इकट्ठा

करके अपनी जेबों में डाल रहे हैं। यह नहीं कि जिन मासूम लोगों की हत्या हुई थी या जो घायल हुए थे यह पैसा उनके घर वालों को दिया जाए। जिन लोगों की हत्या हुई उनके बारे में हमें भी बहुत दुख है। हम उनकी मौत पर दुख प्रकट करते हैं। हम उनके घरों में जाकर भी दुख प्रकट करके आए हैं लेकिन ये लोग दुःख प्रकट करने की बजाए उनके नाम से चन्दा इकट्ठा कर रहे हैं। आज उनमें से कोई एस0वाई0एल0 की बात नहीं करता। अगर उनको पानी की चिन्ता थी तो वे यहां सै ान में आते और अपनी भावनाएं व्यक्त करते। ऐसा करने से उनकी बातें प्रैस में आती और लोगों तक पहुंचती। ऐसा करने की बजाऐ वे गांव–गांव में जाकर चन्दा इकट्ठा कर रहे हैं। किसी गांव में जाते हैं तो 50 हजार की माला पड़ जाती है, किसके नाम से ? भाहीदों के नाम से। यह सारा पैसा भाहीद होने वालों के घर में जाना चाहिए था लेकिन इन्होंने सारा अपनी जेब में डाल लिया। इन लोगों का एस0वाई0एल0 से कोई मतलब नहीं है। जब जनता पार्टी का राज था तो यहां पर चौधरी देवी लाल मुख्य मन्त्री थे और पंजाब में प्रका ा सिंह बादल मुख्य मन्त्री थे। उस समय ये एस0वाई0एल0 पर एक इंच भूमि पर भी काम नहीं करवा सके। लेकिन हमारी सरकार ने इतने खतरनाक हालात में कितना कुछ किया। हमने पंजाब को इस नहर पर आने वाला लगभग सारा खर्च दे दिया है बाकी जो रहता है वह पंजाब का हिस्सा रहता है। इसका मतलब यह है कि मौजूदा हरियाणा सरकार की नीति इस बारे में बिल्कुल स्पश्ट है और यह चाहती है कि एस0वाई0एल0 का पानी हरियाणा

में जल्द से जल्द आए। विरोधी पक्ष तो यह चाहता है कि पानी न आए और समझौता न हो ताकि मुख्य मन्त्री और प्रधान मन्त्री की बदनामी हो और उसका फायदा उन्हें मिले। उधर बरनाला साहब पंजाब के मुख्य मन्त्री हैं और प्रका ा सिंह बादल चाहते हैं कि ऐसे ही हालत खराब रहें जिससे बरनाला साहब की बदनामी हो और उनके हाथ में कुर्सी लग जाए। तो यह सारी बात कुर्सी तक सीमित है। इसलिये इस बारे में हर आदमी को सोचने की जरूरत है। विरोधी पक्ष के लोग यहां की बजाए आज दिल्ली में रैली कर रहे हैं। वे इधर नहर खोदने की तरफ क्यों नहीं आते। अगर वे इस काम के लिए इधर आते हैं तो हम भी उनके पीछे लगेंगे। अगर वे लोग ऐसा करेंगे तभी यह नहर खुदेगी। आज क्या हो रहा है कि पानी पाकिस्तान को जा रहा है और पंजाब की भूमि सेम हो रही है। जब हरियाणा अलग हुआ था तो उस समय हरियाणा को 62% पानी दिया गया था और पंजाब को 100% दिया गया था। उसके बाद जगह–जगह नहरें बन गई। आज हरियाणा में सिर्फ 40% पानी है जबकि पंजाब में 200% है। इसके बावजूद भी बाकी का पानी पाकिस्तान को जा रहा है। ऐसी स्थिति में एक तरफ तो हालत यह है कि पंजाब पानी में डूब रहा है और दूसरी तरफ हरियाणा के खेत सूख रहे हैं। इसलिये पंजाब को इस बारे में सोचना चाहिए कि वह हरियाणा को पानी दे। लेकिन पंजाब की अकाली सरकार ऐसा सोच नहीं सकती और न ही उसकी ऐसी भावना है। उनका मुद्दा यही है कि हमने हरियाणा को कुछ नहीं देना है और हरियाणा से कुछ लेना है। वे हमें

फाजिल्का अबोहर के गांव नहीं देना चाहते लेकिन चण्ड़ीगढ़ लेना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है। चण्ड़ीगढ़ में हरियाणा का 47% पैसा लगा है। कहमे हैं हमें चण्ड़ीगढ़ दे दो और फाजिल्का अबोहर के गांव मत लो बल्कि पटियाला के कुछ गांव ले लो। मैं उनको बताना चाहता हूं कि पटियाला के गांव तो हमें दूसरे कमि ान से अपने आप आ जाएंगे। जो फाजिल्का अबोहर के 105 गांव हैं, उनके बारे में इन्दिरा गांधी ने अपने अवार्ड में कहा था कि ''इन लियू आफ चंडीगढ़'' ये हरियाणा को मिलेंगे। This is what Shrimati Indira Gandhi always maintained. इस अकौर्ड से साफ जाहिर है कि हालांकि अबोहर तथा फाजिल्का क्लीयरली मैं ान नहीं किये गये थे लेकिन इन्टै ान यही थी कि not only the towns of Fazilka and Abohar but also other Hindi speaking villages of that area will be given to Haryana in lieu of Chandigarh. अकौर्ड के समय संत लौंगोवाल ने कहा था कि हालात खराब हैं। इसलिये एकोर्ड में इस बारे में क्लीयरनी नहीं लिखा गया था लेकिन इन्टै ान यही थी। उस टाईम लौंगोवाल जी ने यह भी कहा था कि यह एकोर्ड में मैन् ान न किया जाए। इसलिये एकोर्ड में फाजिल्का अबोहर का नाम ही नहीं था इसलिये ये इलाके हम नहीं देंगे। एक कुडू खेड़ा गांव की वजह से हमें मिलने वाले इतने गांव रोकना चाहते हैं और चण्डीगढ़ जिसमें हमारा 47% पैसा लगा हुआ है उसके बारे में कहते हैं कि पंजाब को दे दिया जाए। इस बारे में केन्द्र सरकार को सोचना पड़ेगा। चण्डीगढ़ के बदले अगर फाजिल्का अबोहर के गांव हरियाणा को न

आएं तो हरियाणा सरकार इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारा इतना स्टैंड होने के बावजूद भी विरोधी पक्ष के भाई कहमे हैं कि अन्याय हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि अन्याय कहां हो गया। वे कहते हैं कि हम हरियाणा के हितों की रक्षा करेंगे। क्या हरियाणा के हितों को वही ठीक समझ सकते हैं ? हरियाणा के हित आज की कांग्रेस सरकार के हाथों में, हमारे मुख्य मन्त्री जी के हाथों में सुरक्षित हैं और हम सभी इस बात के लिए उत्सुक हैं कि हमारा नुकसान न हो। राजीव गांधी जी भी नहीं चाहते कि हरियाणा को नुकसान हो। जो आदमी फैसला करता है वह सभी बातों को सोच समझ कर करता है। बड़ा भाोर था कि 26 जनवरी को चण्डीगढ़ पंजाब को चला जाएगा। चण्डीगढ़ के कर्मचारियों को 25 जनवरी को तनखाह तक दे दी गई थी लेकिन हुआ कुछ नहीं, चण्डीगढ़ वहीं का वहीं रहा। पंजाब वाले आज भी चाहते हैं कि पंजाब में तो जल जला हो जाए और हरियाणा के खेत सूखे रहें। पंजाब के टोटल पानी में से हरियाणा का 47 प्रति ात हिस्सा है। अब जो इसके लिए अरैडी कमि ान बना है, वह न्याय की बात करेगा। हमें 3.5 एम0ए0एफ0 की बजाए 7.5 एम0ए0एफ0 पानी मिलना चाहिए। आज फालतू पानी पाकिस्तान में जा रहा है और पंजाब की धरती में 200 प्रति ात पानी है। हरियाणा में केवल 40 प्रति ात पानी है इसलिये केन्द्र सरकार न्यायोचित बात करे। हम इस रैजोल्यू ान के जरिये केन्द्र सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि एस0वाई0एल0 कैनाल के काम को केन्द्र सरकार खुद अपने हाथ में ले। वरना यह पानी हमें मिलने वाला नहीं है। मै। रिक्वैस्ट

करूंगा कि इस रैजोल्यू ान को आज ही पास किया जाए। इस बारे में मैं मुख्य मन्त्री जी से और सुरजेवाला जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि यह आज ही अव य पास होना चाहिए। हम केन्द्रीय सरकार को यह कहें कि इस काम को वह अपने हाथ में ले और 15 अगस्त तक इस नहर की खुदवाई करवाएं ताकि जो हरियाणा के साथ अन्याय हो रहा है वह खत्म हो। मैं विरोधी पक्ष के लोगों को कहूंगा कि उनको रैली करने की जरूरत नहीं है। यदि उन्होंने रैली करनी है तो वे हरियाणा के लोगों को आपस में मरवाने के लिए रैली न करें। अगर रैली करनी है तो वे पंजाब के कपूरी गांव में रैली करें, मैं कहना चाहता हूं कि रैली नहीं बल्कि नहर की खुदाई का काम करें। वहां पर जा कर नहर को अपने आप खोदें और यदि पंजाब सरकार उनको गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करे। जिस तरह से अपोजी ान के भाईयों ने रैली की है, वह आपस में लड़ने के लिए की है। इस तरह से करके हम आपस में लड़ रहे हैं। हमे आपस में मिल कर उस नहर की खुदाई के बारे में कोई बात करनी चाहिए। मेरे अपोजी ान के भाईयों को बुद्धिमता की बात करनी चाहिए। मेरे विरोधी पक्ष के भाईयों में यह बुद्धिमता होनी चाहिए कि आपस में लड़ने से हरियाणा को न्याय मिलने की बजाय कम होता है। हमें केन्द्रीय सरकार पर यह दबाव डालना चाहिए कि हम वहां रैली करने के लिए जाएंगे जहां पर वास्तव में नहर की खुदाई हो रही है। यहां हरियाणा में रैली करने की बजाय मेरे विरोधी पक्ष के भाई वहां पर नहर खोदने के लिए क्यों नहीं गए। यहां हरियाणा में लोगों से चन्दा इकट्ठा

करने के लिए भागे फिर रहे हैं। मेरे विरोध पक्ष के भाईयों को रैली करने के लिए 300 किलोमीटर दूर दिल्ली में जाने की जरूरत नहीं थी उनको जहां पर नहर की खुदाई होनी है उधर केवल 150 किलोमीटर जाने की जरूरत थी। इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि वे आपस में मिल कर इस बात को सोचें कि उन्हें रैली करनी ही हो तो पंजाब में करें। अकालियों के खिलाफ रैली करें। लेकिन चौधरी देवी लाल जी और सरदार प्रका ा सिंह बादल में यह गठजोड़ है कि चौधरी देवी लाल जी इस सरकार को कमजोर करें और बादल साहब उस सरकार को करें। यह बात उनके हित में नहीं हैं। ऐसा करने से उनको कुर्सी नहीं मिलती। इस बारे में मुझे एक कहावत याद आ गई। एक लड़का अपनी मां से कहने लगा कि मां मुझे नम्बरदारी मिलनी चाहिए उसकी मां ने कहा नम्बरदारी तुझे नहीं, उसको मिलेगी। फिर वह लड़का बोला यदि वह मर जाए तो नम्बरदारी किसको मिलेगी उसकी मां ने कहा यदि वह मर गया तो नम्बरदारी उसको मिलेगी। फिर वह लड़का बोला यदि वह भी मर गया तो फिर नम्बरदारी किसको मिलेगी उसकी मां ने फिर कहा कि उसको मिलेगी। फिर वह लड़का बोला यदि वह भी मर गया तो फिर किसको मिलेगी। उसकी मां ने कहा बेटा चाहे सारा गांव मर जाए तुझे नम्बरदारी नहीं मिलेगी। चौधरी देवी लाल जी और बादल साहब के ऐसा सोचने पर ऐसा नहीं हो सकता। यदि वह ऐसा सोचेंगे कि हम ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। अगर मेरे विरोधी पक्ष के भाइयों ने हरियाणा के हितों की वास्तविक तौर पर रक्षा करनी है तो उनको

यहां असैम्बली में आना चाहिए था। लेकिन वे यहां सदन में कैसे आ सकते थे वे तो रैली में जो मासूम लोग मरे हैं उनके लिए चन्दा इकट्ठा करते फिर रहे हैं। उनके नाम से चन्दा ले रहे हैं। मैं कहता हूं कि जो भी पैसा चन्दे के रूप में उनके पास जमा होगा वह मृतकों के परिवार वालों को मिलना चाहिए। यदि वह पैसा उनके परिवारों को नहीं दिया गया तो उनके खिलाफ कार्यवाही भी हो सकती है। इन भाब्दों के साथ मैं हाउस से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करके केन्द्रीय सरकार को भेजना चाहिए कि केन्द्रीय सरकार एस0वाई0एल0 नहर की खुदाई का काम अपने हाथ में ले ताकि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी जल्दी से जल्दी मिल सके।

वक्तव्य

मुख्य मन्त्री द्वारा सहायता प्राप्त गैर सरकारी महाविद्यालयों के अमले का वेतन बैंकों द्वारा अदायगी संबन्धी।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से पब्लिक हित में एक स्टेटमैंट देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में प्राइवेट कालेजों के अध्यापकगण तथा अन्य स्टाफ के वेतन के संबंध में उल्लेख किया गया। कुछ कठिनाईयों का उल्लेख पिछले कई वर्शों से सदन में किया गया तथा इस विशय पर चर्चा हुई। इन विद्यालयों के अध्यापकगण एवं अन्य स्टाफ को वेतन मिलने में आने वाली

कठिनाईयों पर सरकार ने गंभीरता से विचार किया है। कल इस विशय में इन कालेजों की मैनेजमैंट, प्रधानाचार्यों से तथा अध्यापकगण व स्टाफ के प्रतिनिधियों से विस्तार से चर्चा की गई। सौभाग्यव ा चर्चा के फलस्वरू सभी पहलुओं पर आम सहमति हुई जो मुख्य निर्णय लिये गए उनको मैं सदन के सम्मुख माननीय सदस्यों की सूचना के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं :–

1. राज्य में गैर–सरकारी कालेजों के प्रधानाचार्यों, अध्यापकों तथा अन्य स्टाफ को वेतन बैंक के माध्यम से दिया जाएगा।

2. यह योजना 1–4–1986 से लागू होगी।

3. क्योंकि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार इन कालेजों के घाटे की 95 प्रति ात की प्रतिपूर्ति सरकार करती है अतः 5 प्रति ात का दायित्व इन कालेजों के मैनेजमैंट का ही पहले की तरह रहेगा।

4. 1985–86 वर्श का घाटा पूरा करने का सरकार का कानूनी दायित्व तो नहीं है लेकिन मैनेजमैंट तथा कालेजों की परे ाानी देखते हुए सरकार अगले पांच वर्शों में दस छमाही कि तों मं यह रा ि ा इन कालेजों को प्रदान करेगी।

5. इन कालेजों की वित्तीय स्थिति की पूरी सूचना सरकार को तत्काल दी जायेगी और जो इनके असैट्स 19–2–1986 को थे, उन में किसी प्रकार की कमी इन की

मैनेजमैंट या कालेज के प्र ाासक बिना सरकार की अनुमति के नहीं करेंगे।

6. इन कालेजों के प्र ाासन का दायित्व पहले की तरह मैनेजमैंट का ही होगा और उसमें सुगमता लाने के लिए तथा अनु ाासन बनाये रखने के लिये अध्यापकगण एवं अन्य स्टाफ की वार्शिक गोपनीय रिपोर्ट लिखी जाएगी।

मुझे वि वास है कि इन निर्णयों से प्राइवेट कालेजों के अध्यापकों तथा अन्य स्टाफ में जो निरा ाा थी, वह दूर होगी और पढ़ाई का स्तर और ऊंचा उठेगा। जहां तक इनके मैनेजमैंट का ताल्लुक है हमें वि वास है कि वे अपने दायित्व को भली–भांति निभाते रहेंगे, जैसे पहले निभाते रहे हैं।

उक्त निर्णय के अनुपालन के लिए सरकार को कुछ और व्यवस्था विस्तार से करनी होगी। इस पर विचार भ्ारू कर दिया गया है ताकि यह योजना 1–4–1986 से सुचारू रू‍प से चलाई जा सके। मैं मैनेजमैंट के प्रतिनिधि, प्रधानाचार्यों, अध्यापकगण तथा अन्य स्टाफ के प्रतिनिधियों को बधाई देता हूं जिन्होंने बहुत सूझ–बूझ से हमें चर्चा में सहायता दी है। इस चर्चा में और निर्णय लेने में मेरे साथी वित्त मन्त्री श्री सागर राम गुप्ता एवं ि ाक्षा मन्त्री श्री जगदी ा नेहरा का भी वि ोश योगदान रहा है।

गैर सरकारी प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सदन में एस0वाई0एल0 कैनाल के बारे में चर्चा चल रही है। इस कैनाल के बारे में सभी माननीय सदस्यों की भावनाएं उत्तेजित हैं और सभी माननीय सदस्यों की भावनाएं और विचार एक हैं कि एस0वाई0एल0 कैनाल जल्दी बननी चाहिए। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यदि इस प्रस्ताव पर एक या दो सदस्य और बोल लें, उसके बाद बाकी जो और काम हैं, वे हो सकें तो अच्छा रहेगा। आपके पास बहुत दूर–दूर से लोग अपने काम करवाने के लिए आए होंगे उनका काम करवाएं। मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज की कार्यवाही जल्दी समाप्त कर लें। एक या दो और सदस्य जो बोलना चाहें, वह बोल लें।

श्री रो ान लाल आर्य (छछरोली) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव सदन के विचाराधीन है इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारे हिस्से का पानी पंजाब से इधर नहीं आ रहा है। मैं इस बात से हैरान हूं कि जो हरियाणा के हिस्से का पानी है, वह पंजाब में है इसके बावजूद भी पंजाब में जो आग सुलग रही है, वह बुझने का नाम नहीं ले रही है। मैं हरियाणा सरकार को इस बात के लिए इस मौके पर बधाई देता हूं कि हमें हमारे हिस्से का पानी न मिलने के बाद भी और यहां पर हालात खराब होते हुए भी उसने हरियाणा में आग लगने दी। उधर पंजाब हमारे हिस्से का पानी ले कर भी पंजाब में लगी हुई आग पर काबू

पाने में सक्षम नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जब आज सुबह मैंने अखबार पढ़ा तो आंखों में खून उतर आया कि किस तरीके से पंजाब में बेगुनाह आदमियों को प ुओं की तरह मार दिया गया है। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि पंजाब में पिछले साल इतने प ु नहीं मरे होंगे जितने वहां पर बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया है। पंजाब में बेगुनाह लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा गया है। दुनिया के इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जिस तरह से पंजाब में लोगों को मारा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सदन को इस बात पर गहरी चिन्ता प्रकट करनी चाहिए जो आज पंजाब में हो रहा है। जहां हम आज यह प्रस्ताव पास कर रहे हैं कि हमें हमारे हिस्से का पानी मिलना चाहिए और केन्द्र को नहर निर्माण का कार्य अपने हाथ में लेना चाहिए वहां केन्द्र को इस बात के लिये भी ठोस कदम उठाने चाहिए कि पंजाब में जो उग्रवाद का राक्षस बेगुनाह नागरिकों को मार रहा है, उसको भी कंट्रोल किया जाए। पानी के साथ–साथ यह भी बहुत जरूरी मसला है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पंजाब समझौता किया गया था, वह राजीव गांधी और संत लौंगोवाल के बीच हुआ था। समझौता इसलिए हुआ था ताकि पंजाब में किसी तरीके से भाांति स्थापित हो। लेकिन पंजाब में भाांति स्थापित होने का नाम नहीं है, आग और भी तेजी से भड़क रही है। आज पंजाब में आवाज उठती है कि क्यों नहीं जल्दी से जल्दी राजीव–लौंगोवाल समझौता लागू किया जाता। लेकिन पंजाब वाले उस समझौते का मतलब

केवल चण्डीगढ़ हथियाओ समझौता मानते हैं। केवल यह चाहते हैं कि उनको जो कुछ चाहिए वह तो उनको तुरन्त मिल जाए और हरियाणा को कोई भी चीज न मिले, पानी की एक बूंद भी न मिले। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस सृश्टि के निर्माण करने वाले भगवान का यह नियम है कि जो भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का हिस्सा मारता है, उसकी नीयत खराब होती है, उसके यहां कोई बरकत नहीं हो सकती। वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता और न कोई लाभ उठा सकता है। मैं सोचता हूं कि कहीं हरियाणा की जो प्यासी धरती है भाायद उसकी बद्दुआओं की वजह से पंजाब में आग न सुलग रही हो। मेरी जो भावनाएं थीं, वह मैंने आपके जरिए हाउस में कह दी हैं। पंजाब में जो हमारे भाई मारे जा रहे हैं, उनके लिए हमें रोश प्रकट करना चाहिए। पंजाब में जो हमारे भाई मारे जा रहे हैं उनके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए और वातावरण को जागृत करना चाहिए ताकि जो घटनाएं वहां घट रही हैं वे न घटें। हमें वहां के लोगों की जान–माल की रक्षा करने के लिए कोई न कोई कदम उठाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक नहर के निर्माण का संबंध है, उस बारे में मुझे अपनी सरकार से पूरी उम्मीद है कि यह जल्दी से जल्दी बन कर तैयार हो जायेगी। मुख्य मन्त्री जी ने भी कई बार बयान दिया है कि इस नहर का निर्माण कार्य केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। अन्त में मैं सारे हाउस

से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रस्ताव को पास किया जायें। हरियाणा को अपने पानी का उचित हिस्सा मिले ताकि हरियाणा भी ज्यादा से ज्यादा विकास कर सके। केन्द्र सरकार से मांग की जाये कि जो हरियाणा के हिस्से का पानी है, बिजली है और टैरीटरी है, वह हमें मिले ताकि यहां पर और पंजाब में भी भाान्ति स्थापित हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्र न पर काफी सदस्यों ने अपने विचार क्वै चन आवर में भी जाहिर किए हैं और इस पर सब की एक ही राय है। जो सदस्य बोलने के इच्छुक हों, वह बजट पर बोल लें।

12.00 बजे

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से इस प्रस्ताव के बारे में संक्षेप में दो–चार बातें कहना चाहूंगा। इस प्रस्ताव पर इस विधान सभा के 3 सदस्यों ने बहुत विस्तार से अपने विचार प्रकट किए हैं। इस प्रस्ताव को श्री इन्द्र सिंह नैन ने पे ा किया था और उन्होंने अपने विचार काफी विस्तार से प्रकट किए। नैन साहब के बाद श्री नेहरा और श्री आर्य साहब ने भी अपने–अपने विचार प्रकट किए। इन तीनों सदस्यों के बोलने के बाद मैं समझता हूं कोई बात नहीं रह जाती, जिसका जिकर न आया हो। आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं कि काफी सदस्य

अपने विचार इस बारे में प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि रैपिटी ान का और बार–बार एक ही बात को दोहराये जाने का कोई लाभ नहीं होगा। हाउस की जो राय है वह बहुत ज्यादा जाहिर है और मैम्बरों में भी बहुत जज़बा है। इसलिए हाउस की राय को देखत हुए और मैम्बरों की राय को देखते हुये सरकार ने फैसला किया है कि इस प्रस्ताव पर आज ही वोटिंग करवा ली जाये और प्रस्ताव को पारित कर दिया जाये। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा कि कितना अच्छा होता यदि आज अपोजी ान के साथी सदन में उपस्थित होते और अपनी इच्छा जाहिर करते। बड़े अफसोस की बात है कि अपोजी ान के भाई अपनी जिम्मेवारी से भाग गए हैं। उन्होंने जो अपना कर्तव्य निभाना चाहिए था, वह नहीं निभाया। उपाध्यक्ष महोदय, नहर के निर्माण के बारे में मैम्बरों ने काफी कुछ कह दिया है। अब मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता। इस बात का जिकर मैं अव य करना चाहूंगा कि जब ये भाई सवा दो साल या अढ़ाई साल तक सत्ता में रहे, उस समय इनकी तरफ से या अकालियों की तरफ से कभी कोई एजिटे ान नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब चौधरी देवी लाल जी मुख्य मन्त्री थे, उस समय उन्होंने नहर के निर्माण के बारे में कोई एजिटे ान नहीं किया। जिस समय उनका राज था उस समय इस नहर के निर्माण की कौस्ट सिर्फ 45–46 करोड़ रुपये ही थी। इससे ज्यादा खुदाई की कौस्ट नहीं थी। उससे ज्यादा सुनहरी अवसर हरियाणा के लिए और कोई नहीं हो सकता था। यदि उस समय

यह नहर बना दी जाती तो आज इतना अधिक खर्चा न होता। इससे जाहिर है कि उनकी नीयत इस काम के प्रति सीरियस नहीं थी। उस समय नहर की खुदाई न कराये जाने का उनके पास कोई जवाब नहीं है। कितना अच्छा होता यदि आज वे हाउस में उपस्थित होते और यह बताते कि हम सवा दो साल में इस नहर का निर्माण क्यों नहीं करा पाये। उन्हीं को वजह से हरियाणा का अहित हुआ है, इसीलिए वे हाउस में उपस्थित नहीं हो रहे। इन्होंने एस0वाईएल0 का पानी लाने में अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं निभाई। आप को पता है कि पीछे दो दफा भांखड़ा मेन लाईन में ब्रीच हुआ था। उस समय अपोजी ान पार्टी का कोई भाई भी मौके पर नहीं गया था। उस समय पंजाब में हालात काफी खराब चल रहे थे। ब्लू स्टार के पहले भी ब्रीच हुआ था। सारे पंजाब में कर्फ्यू लगा हुआ था। जब भाखड़ा में ब्रीच हुआ तो उस समय सिरसा, फतेहाबाद आर हिसार के इलाकों में पानी नहीं पहुंचा था। सरकार ने पूरी कोि ा ा करके यमुना से और दूसरी जगहो से पानी लेकर इस एरिया में पानी पहुंचाया और लोगों को बैगर पानी के नहीं रहने दिया। सरकार ने एक–एक गांव में टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया और 10–10 तथा 20–20 किलोमीटर की टैम्पोरेरी लाइनें लगा कर उस इलाके के लोगों तक पानी पहुंचाया। घग्घर वगैरा छोटी नदियों से पानी हमने लेकर वहां के रजबाहों में पहुंचाया ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। इसके विपरीत विरोधी पक्ष के सदस्य चौधरी देवी लाल समेत कोई भी उस इलाके में नहीं पहुंचा जहां पानी की कमी हो गई थी,

हालांकि वे इलाके उन्हीं के थे। चौधरी देवी लाल जी ने उस समय इस नहर के निर्माण के लए पंजाब को सिर्फ एक करोड़ रुपया ही दिया था जबकि काम एक इन्च भी नहीं हुआ था। इस सरकार ने इस नहर के निर्माण के लिए अब तक पंजाब को 110–112 करोड़ रुपये दिए हैं। नहर के निर्माण को तेज कराने के लिए भारत सरकार और पंजाब सरकार के लैबल पर कोि ा ा की है ताकि नहर के निर्माण में गति आये। यह रिकार्ड की बात है। विरोधी पक्ष का कोई भी सदस्य आज तक इस हाउस से बाहर नहीं गया। उन्होंने मौके पर जा कर नहीं देखा कि कहां नहर बन रही है, कब पूरी होगी और क्या–क्या रूकावटें नहर के निर्माण कार्य में है। अक्टूबर और नबम्बर के महीने में जब भारतीय किसान यूनियन के नेताओं तथा पंजाब के भाइयों ने धरना भुरू किया तो हमने अखबारों में यह बात कही थी कि विरोधी पक्ष के भाई चौधरी देवी लाल समेत सब को चाहिए था कि वे पंजाब के भाइयों को मनाते कि भाई आप आन्दोलन न करें। आज ये किसानों के हितैशी बने फिरते हैं। उनको पंजाब के किसानों को समझाना चाहिए था कि पंजाब के किसानों में और हरियाणा के किसानों में कोई फर्क नहीं है लेकिन उनको हरियाणा के हितों से कोई सरोकार नहीं है और न उनके पास अपना कोई प्रोग्राम है। उन्होंने कभी भी भारत सरकार के लैबल पर, पंजाब सरकार के लैबल पर या किसानों के लैबल पर कहीं कोई बात सैटल करने की कोि ा ा नहीं की। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कोई सुझाव या प्रयत्न नहीं किए। सिवाय लोगों को गुमराह करने

के, उनका और कोई प्रोग्राम नहीं है। मैं संक्षेप में उनकी कारगुजारी के बारे में आप को बताना चाहता था। उपाध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट के ढांचे में उन लोगों का कितना वि वास है, वह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। चौधरी देवी लाल 1982 के इलैक् ानों में जीतकर एम0एल0ए0 बनने के बाद एक बार हाउस में यह बात कहने के लिए आए थे कि पंजाब में अकालियों को सरकार सौंप दी जानी चाहिए। उन्होंने यह बात उस समय कही जब पंजाब में अकालियों का कोई बहुमत नहीं था और उन्होंने अपने इस्तीफे भी दिए हुए थे। वे सिर्फ ये भाब्द कहने के लिए ही असैम्बली में एक दिन आए थै इसके अलावा उन्होंने और कोई बात नहीं की।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि नहर के निर्माण के काम की क्या प्रगति है, हालांकि इस बारे में पहले भी काफी विस्तारपूर्वक बताया जा चुका है। अब मैं थोड़े से भाब्द और कहना चाहूंगा और हाउस के सदस्यों को वि वास में लेना चाहूंगा। जैसा कि सबको पता है, इस नहर की रिवाइज्ड लम्बाई 120 किलोमीटर है। मैंने पहले भी बताया था कि 70 किलोमीटर रीचिज में अर्थ वर्क मुकम्मल हो चुका है या मुकम्मल होने के करीब है। बाकी रिचिज में कोई काम नहीं हुआ है। अगर माननीय सदस्य क्युबिक मीटर्ज में यह बात जानना चाहें तो टोटल अर्थ वर्क 429 लाख क्युबिक मीटर होना था जबकि कुल अर्थ वर्क 178 लाख क्युबि मीटर हुआ है। टोटल कंक्रीट लाइनिंग

53.62 लाख स्केयर मीटर्ज होनी है लेकिन 0ण्45 स्केयर मीटर हुई है। यह तकरीबन टोटल काम की परसैंट है। 11 मेजर क्रौस ड्रेनेज वर्कस में से 5 के ऊपर काम भाुरू किया गया है बाकी के ऊपर काम भाुरू नहीं किया गया है। घ्गर रीवर क्रौसिंग के ऊपर भी काम भाुरू नहीं किया गया है। 42 मीडियम क्रौस ड्रेनेज वर्कस में से 22 के ऊपर काम भाुरू किया गया है। 3 रेलवे पुलों में से सिर्फ एक रेलवे पुल पर काम भाुरू हुआ है। इस कैनाल पर 4 ए0आर0 ब्रिजिज, 8 डिस्ट्रिक्ट रोड़ ब्रिजिज और 56 विलेज रोड़ ब्रिजिज बनने हैं लेकिन प्रैटिकली किसी पर काम भाुरू नहीं किया गया है। हरियाणा ने अब तक 110.5 करोड़ रुपया नकद दिया है और 2.8 करोड़ रुपये की म ानरी दी है। इसमें से अभी भी प्रोजैक्ट अथैरिटीज के पास 30 करोड़ रुपया अनस्पैन्ट पड़ा है। टोटल रिवाइज्ड ऐस्टिमेटस के बारे में मैंने कल भी हाउस में अर्ज किया था कि सी0डब्ल्यू0सी0 ने 270 करोड़ रुपया ऐक्सैप्ट किया है लेकिन हमें इस बारे में आपत्ति है। हमारे ख्याल से खर्चे का टोटल ऐस्टिमेट 230 करोड़ के करीब बनना चाहिए। अगर 270 करोड़ रुपये के हिसाब से भी कैलकुले ान करें तो हरियाणा का भोयर 225 करोड़ रुपये बनता है और पंजाब का भोयर 45 करोड़ रुपये बनता है। हमने अभी तक 110.5 करोड़ रुपये दे दिया है जबकि पंजाब ने 13 करोड़ रुपये दिया है और 32 करोड़ रुपये अभी देना है। हरियाणा ने 1985–86 में 70 करोड़ रुपये का प्रोवीजन किया था और 1986–87 में 90 करोड़ रुपये का प्रोवीजन किया है। भारत सरकार से हमने यह बात भी कही है कि वह हमें

प्लान अस्सिटैंस के तौर पर रुपया दे दें और बाद में रिकवर कर ले। स्पीकर साहब, कल मैम्बर्ज साहेबान ने यह भांका जाहिर की थी ि कइस नहर पर जो रुपया खर्च हुआ है वह ठीक खर्च हुआ है या नहीं और उसे देखने के लिए सरकार क्या इन्तजाम कर रही है। हरियाणा सरकार ने स्वर्गीय प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय में भी और मौजूदा केन्द्रीय सरकार से भी इस बारे में कई बार प्रार्थना की है और पत्र भी लिखे हैं। पंजाब सरकार को भी इस बारे में लिखा गया है। पंजाब के मुख्य मन्त्री तथा गवर्नर साहब को मुख्य मन्त्री जी ने मिल कर और पत्र व्यवहार से यह बात कही है कि इस नहर का काम जल्दी होना चाहिए। हमारे ऑफिसर्ज भी इस बात के लिए निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं। इस नहर की खुदाई के काम को रिव्यू करने के लिए भारत सरकार ने एक प्रोग्रैस रिव्यू कमेटी नाई है। यह कमेटी 1981 के ऐग्रीमैंट के नीचे बनाई गई थी। इस कमेटी को सी0डब्ल्यू0सी0 के मैम्बर चेयर करते हैं। इसमें पंजाब और हरियाणा के इरीगे ान सैक्रेटरीज, फाइनैंस सैक्रेटरीज और चीफ इंजीनियर्ज मैम्बर्ज हैं। यह कमेटी मौके पर जाकर भी प्रोग्रैस को रिव्यू करती है। इसके अलावा एक और कमेटी है जिसको गवर्नमैंट औफ इंडिया, मिनिस्ट्री औफ वाटर रिसोर्सिज के सेक्रेटरी चेयर करते हैं। इसकी पीरियोडिकल मीटिंग्ज होती रहती है। पिछले दिनों, दिसम्बर के महीने में इस कमेटी के जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं, उन्होंने इस नहर का दौरा किया था और यह रिपोर्ट दी है कि वे काम की प्रोग्रैस से संतुश्ट नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने नहर के बारे में जो

पत्र व्यवहार किया है उसके बारे में मैं संक्षेप में हाउस को बताना चाहूंगा क्योंकि पूरा ब्यौरा देना, सारी बात को डिसक्लोज करना न तो सरकार के हित में है, न प्रोजैक्ट की कम्पलि ान के हित में है और न ही हरियाणा के हित में है। हरियाणा सरकार ने गवर्नमैंट औफ इंडिया से तीन मांगे की है। एक मांग तो यह है कि इस प्रोजैक्ट की ऐक्सिक्यू ान का काम गवर्नमैंट औफ इंडिया अपने हाथ में ले ले। हमने इसके लिए पूरी वजह उनसे ब्यान की है क्योंकि अब तक पंजाब सरकार इस काम को ठीक से करने में नाकामयाब रही है और इस बात का कोई चांस नहीं है कि यह काम समय से मुकम्मल हो सके। दूसरी मांग हमारी है कि इस प्रोजैक्ट पर जो खर्च होना है वह इनि ियली भारत सरकार कर ले और जब इसका लाभ मिलना भुरू हो जाए तो हमारे हिससे के पैसे को कि तों में हमसे वसूल कर लिया जाए। तीसरी बात हमने यह कही है कि जो खर्चा हुआ है उसकी स्क्रुटनी के लिए कोई तरीका बनाया जाए और स्क्रूटनी के बाद जो रुपया ऐसा निकले जिसे पंजाब सरकार ने खर्च नहीं किया है, उसे पंजाब के खाते से काट लिया जाए। हम भारत सरकार सेयह भी मांग करने जा रहे हैं कि कम्पट्रोलर एंड औडिटर जनरल औफ इंडिया से जितना रुपया अब तक खर्च हुआ है उसकी ठीक ऐप्लीके ान के बारे में स्पै ाल औडिट करवा लिया जाए। वैसे तो पंजाब गवर्नमैंट के इन्टरनल औडिट सिस्टम से इसका औडिट होगा लेकिन उससे हमारी तसल्ली नहीं होगी।

स्पीकर साहब, मैं ज्यादा समय न लेकर के लास्ट में इतना कहना चाहूंगा कि जहां तक इस नहर के समय से पूरा होने की बात है, उसके लिए मुख्य मन्त्री जी एक दफा नहीं बार–बार यह बात इम्प्रैस अपोन कर चुके हैं, प्रधान मन्त्री जी से, भारत सरकार के जो दूसरे संबंधित मन्त्री और अधिकारीगण हैं, उनसे यह बात कह चुके हैं, कि इस नहर को भारत सरकार स्वयं बना लेक्योंकि इस बात का चांस बहुत कम है कि पंजाब सरकार इस काम को तेजी से कर सके। अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी यहां इस बात की चर्चा की थी कि हरियाणा सरकार ने बार–बार इस बात पर जोर दिया है कि पंजाब सरकार पहले जमीन को ऐक्विजि ान कर ले। जून 1985 में सुरेन्द्र नाथ जी पंजाब के गवर्नर साहब के ऐडवाइजर थे और नहर के महकमे का काम देखते थे। उनसे जब हमने कहा था कि पंजाब गवर्नमैंट ने 45 करोड़ रुपया खर्च नहीं किया तो वे आए और उनसे हमारी मीटिंग हुई तथा यह फैसला हुआ कि पंजाब सरकार अपने हिस्से का पूरा रुपया देगी। यह भी तय हुआ था कि जो रुपया हरियाणा सरकार देगी तथा पंजाब सरकार देगी उससे सबसे पहले किसानों को मुआवजा देकर के जमीन ऐक्वायर की जाएगी। इसके बाद पंजाब सरकार बार–बार कहती रही कि नहर का काम तेजी से चल रहा है और वक्त पर पूरा हो जाएगा लेकिन हाउस को पता है कि असल स्थिति क्या है। 2 जनवरी, 1986 को मैं अपने अधिकारियों के साथ मौके पर गया और पूरी कैनाल को देखा। मैं माननीय प्रैस के प्रतिनिधियों को भी साथ लेकर गाय था। और उसके बाद आज तक पंजाब

सरकार ने और बरनाला जी ने यह बात नहीं कही कि यह नहर 15 अगस्त तक पूरी हो जायेगी। भारत सरकार पूरी तरह संतुश्ट है कि पंजाब सरकार और अकाली दल नहर को पूरी नहीं करवायेंगे। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द भार सरकार और स्वयं प्रधान मन्त्री जी इस बारे में कारगर उपाय करेंगे जिससे यह नहर बन सके। प्रधान मन्त्री स्वयं इस बारे में उत्सुक हैं कि यह नहर जल्दी बने। प्रधान मन्त्री और भारत सरकार चाहती है कि कोई ऐसा तरीका निकले जिससे यह नहर अगर 15 अगस्त तक न बन सके तो इस साल के अन्त तक जरूर पूरी हो। इन भाब्दों के साथ मैं मैम्बरान से उम्मीद करूंगा कि वे अपना सही मत व्यक्त करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्र न है–

"This House recommentds to the State Government to approach the Central Government to immediately take over the construction of the S.Y.L. Canal in the Punjab Territory in their own hands so that the same is completed without any further delay. The delay in the construction of the said canal has already greatly affected the economy of the State and increasing the cost of construction thereof tremendously."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Mr. Deputy Speaker: The resloution is unanimously carried.

अब हाउस कल सुबह साढ़े नौ बजे तक के लिए एडजर्न किया जाता है।

12.02 बजे

(तत्प चात् सदन भाुक्रवार, 21 फरवरी, 1986 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।)